

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

88/5172

सं० ५८] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च १६, १९७२/फाल्गुन २६, १८९३

No. 58] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1972/PHALGUNA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**बजट १९७२-७३**  
**वित्त मन्त्री का भाषण**  
**१६ मार्च, १९७२**

महोदय,

मैं चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और १९७२-७३ के बजट अनुमान पेश करता हूँ।

आर्थिक स्थिति : १९७१-७२

२. जो वर्ष अब समाप्त होने जा रहा है, वह कई दृष्टियों से हमारे हाल के इतिहास का सबसे अधिक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष का प्रारम्भ जनता के उस संकल्प की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हुआ जो उसने समाजिक न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर होने के साहसपूर्ण और क्रान्तिकारी कार्यक्रम के पक्ष में किया था। इस निर्णय की हाल ही में हुए विधान सभाओं

के चुनावों में स्पष्ट रूप से पुनः पुष्टि हो गई है। किन्तु वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्व बंगाल में आतंक और अत्याचार का शासन भी देखने को मिला। नवम्बर, 1971 तक, कोई एक करोड़ शरणार्थियों ने हमारे यहां शरण ली; और हमने भी इन अभागों किन्तु बहादुर लोगों की देखभाल करने में कोई कोरकसर नहीं रखी। इस प्रकार भारी संख्या में शरणार्थी आ जाने और एक अनचाहा युद्ध छिड़ जाने के खर्च के बावजूद, हमने यह निश्चय किया कि विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों में जो कि उसने ही अनिवार्य थे किसी प्रकार की देरी या ढील न की जाए। इसके विपरीत हमने खर्च के अतिरिक्त बोझ को संभालने के लिए दो अनुपूरक किस्तों में नए कर लगाए, स्वीच्छिक बचतों के रूप में अधिक धन जुटाया और आयोजना-भिन्न व्यय में किराया करने तथा तेजी से कर इकट्ठे करने के अभियान को नया रूप दिया।

3. सर्वोपरि बात यह है कि हमने जनता की एकता के बल पर इस चुनौती का सामना किया; और अब यह संभव हो गया है कि हम आर्थिक क्षेत्रों में भी गत वर्ष की घटनाओं पर कुछ आत्म-विश्वास के साथ नज़र डाल सकते हैं। कुछ ऐसे असाधारण वबावों और तनावों के बावजूद, जो देश के अनेक भागों में दैवी विपत्तियां आ जाने के कारण और अधिक बढ़ गए थे, चालू राजस्व वर्ष के अन्त में स्थिति यह है कि हमने अपनी विदेशी मुद्रा की संचित राशि को सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि कुछ बढ़ाया भी है, अनाज के सरकारी भंडार में लगभग 80 लाख टन अनाज है, सामान्य मूल्यों के स्तर में पर्याप्त स्थिरता है और केन्द्रीय बजट में जितने घाटे की आशंका की जा सकती थी उससे काफी कम घाटा रहा है।

4. गत वर्ष की घटनाएं, कुछ हद तक, आगामी महीनों में भी अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी। सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि हमें बंगला देश की मिला जनता को और वहां की सरकार को उनके पुनर्निर्माण और पुनर्वास के तात्कालिक कार्य में सहायता देनी है। हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था के संचित भंडार में से जो कुछ निकाला है और हमारी उत्पादक परिसम्पत्तियों को भी जो असाधारण नुकसान पहुंचा है उसे पूरा करना है। किन्तु सर्वोपरि बात यह है कि अब जबकि शरणार्थी अपने-अपने घरों को लौट गए हैं, हमें अपने देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को अधिकाधिक मात्रा में लगाना है। हालांकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने जो लोच और मजबूती दिखाई है उससे हमें विश्वास की भावना पैदा होती है, फिर भी संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. पिछले दिनों की आर्थिक स्थिति में कई ऐसी निर्देशक बातें हैं जो उन क्षेत्रों की ओर संकेत करती हैं जहां आगे प्रयत्न जारी रखना जरूरी है। इनके विषय में 'आर्थिक समीक्षा' में कुछ विस्तार से विचार किया गया है। आर्थिक विकास की गति 1971-72 में धीमी रही है। कुछ हद तक यह बात समझी जा सकती है क्योंकि शुरू के वर्षों में मुख्य दाल-भिन्न अनाजों के उत्पादन की वृद्धि जिस ऊंची दर से हुई थी वह दर हर वर्ष कायम नहीं रखी जा सकती और वास्तव में उसे कायम रखना जरूरी भी नहीं। परन्तु इस प्रवृत्ति को दालों, वाणिज्यिक फसलों और समग्र उद्योगों के उत्पादन की दर में वृद्धि करके प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए। अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारे बहुत से बुनियादी उद्योग, विशेष रूप से इस्पात और उर्वरक उद्योग अपनी क्षमता से काफी नीचे चल रहे हैं। कृषि सम्बन्धी कच्ची सामग्री की कमी के कारण वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल जैसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता माल का उत्पादन करने वाले उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह जानकर तो प्रोत्साहन मिलता है कि बहुत से पूंजीगत माल बनाने वाले और महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों के उत्पादों की मांग बहुत अधिक है और उनके उत्पादन की दर संतोष-जनक खली आ रही है। परन्तु यहां भी प्रगति सर्वत्र समान रूप से

अच्छी नहीं है। हमें बेहतर प्रबन्ध, पहले से अधिक क्षमता का उपयोग, कच्चे माल की मांग में वृद्धि और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार तथा अधिक सक्रिय मांग के सामान्य अपेक्षावर्णन से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं को तो सुलझाना ही है, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का निर्माण भी तत्परता से करना है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ हैं :—विजली उत्पादन और उर्वरक तथा इस्पात उद्योगों के क्षेत्र, जहां विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग कर लेने मात्र से ही अधिक समय तक मांग पूरी नहीं की जा सकेगी।

6. अन्य भी कई प्रवृत्तियां हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। खाद्यान्नों से भिन्न वस्तुओं का आयात तो तेजी से बढ़ा है, परन्तु निर्यात के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। इसके परिणामस्वरूप चालू राजस्व वर्ष में आयात-निर्यात का व्यापारिक अन्तर (ट्रेड गैप) काफी बढ़ जाने की सम्भावना है। सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न कार्यक्रम पिछले दो वर्षों में प्रारम्भ किए गए हैं, उनमें अभी गति आनी है। इसके अलावा, सुधार के कुछ चिन्ह दिखाई देने के बावजूद सरकारी और गैर-सरकारी दोनों उद्योग-क्षेत्रों में बचत और निवेश का स्तर, विकास की दर को संतोषजनक बनाये रखने की दृष्टि से अपर्याप्त है।

7. यदि आत्मनिर्भर होने और सामाजिक न्याय के साथ विकास करने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना है तो इस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन लाना होगा। लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि किए बिना, एक उचित अंश तक मूल्यों में स्थिरता लाना भी संभव नहीं है। विकास सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, पुंजीनिवेश और साधन-संग्रह—सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कुछ हद तक, और वास्तव में उस सीमा से काफी आगे तक जहां तक आमतौर पर समझा जाता है, एक दूसरे को संबल देती हैं। हमें अपनी बजट सम्बन्धी और अन्य नीतियों में समुचित परिवर्तन लाकर इन प्रक्रियाओं की गति को तेज भी करना है। हमारी आर्थिक समस्याओं पर समन्वित और सम्मिलित तरीके से विचार करने के उद्देश्य से ही अभी हाल में आर्थिक नीति विषयक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है।

संशोधित अनुमान : 1971-72

8. जहां तक चालू वर्ष 1971-72 के बजट का सम्बन्ध है, सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि शरणार्थी-सहायता के लिए गत मई मास में जो 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे बाद में दो मौकों पर बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए कुल 360 करोड़ रुपये करना पड़ा था। इस व्यवस्था में से अब 325 करोड़ रुपये वस्तुतः खर्च होने का अनुमान है। बाहर से मिलने वाली उस सहायता का ठीक-ठीक हिसाब देना इस समय कठिन है जिससे अन्ततोगत्वा उस खर्च की प्रतिपूर्ति होगी, जो हमने खुद किया है। शरणार्थियों के लिए हमें जो सहायता मिल चुकी है या इस समय मिल रही है उसका काफी बड़ा भाग पहले से ही बंगला देश को दिया जा रहा है। परन्तु भोटा हिसाब यह है कि 325 करोड़ रुपये के बजट-परिचय्य में से 120 करोड़ रुपये तक की राशि बाहरी सहायता से मिल सकती है।

9. हमने चालू वर्ष में ही काफी बड़ी मात्रा में सहायता देकर बंगला देश को सहायता देने के अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। बंगला देश को अब तक लगभग 130 करोड़ रुपये की सहायता के बचन दिए गए हैं; इस राशि में 20 करोड़ रुपये की वह नकद अदायगी

भी शामिल ~~ह~~ पुनर्वासि बजट में से की जा रही है। हमारा इरादा है कि इस सम्बन्ध में कुल 200 करोड़ रुपये की सहायता के बचनों के लिए व्यवस्था की जाए जिसमें से 82 करोड़ रुपये 1971-72 में दिया जाए और शेष राशि 1972-73 में।

10. अब अनुमान है कि 1971-72 का रक्षा व्यय 1411 करोड़ रुपये होगा जब कि इसके लिए बजट में 1241 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी; इस प्रकार इसमें 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। दैवी विपत्तियों में सहायता की मद में 90 करोड़ रुपये का व्यय भी 50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक होगा।

11. आयोजनागत योजनाओं के व्यय की वास्तविक प्रवृत्ति कुछ मित्र-जुली है, और सम्भव है कि चालू वर्ष में आयोजना के व्यय में कुछ कमी हो। परन्तु यह विश्वास करना सकारण है कि यह कमी उतनी अधिक मात्रा में नहीं होगी जितनी आयोजना के पहले दो वर्षों में हुई थी। इस्पात, उर्वरक, पेट्रोल-रसायन और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन में गति आ गई है। 1970-71 के बजट के अन्तर्गत सामाजिक कल्याण की दृष्टि से जो कार्यक्रम चालू किये गए थे उनके बारे में भी यह बात सत्य है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो दो बड़े कार्यक्रम पिछले बजट में शामिल किए गए थे उनको कुछ समय तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और ऐसी संभावना है कि उनका वास्तविक खर्च, 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था से काफी नीचा रहेगा। चालू वर्ष में हमें जो अनुभव हुआ है उससे एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रगति की रफ्तार, केवल वित्त व्यवस्था कर देने से ही कायम नहीं रह सकती। इसके लिए ठीक समय पर परियोजनाओं का रूपांकन और चुनाव करना तथा तेजी के साथ उनका कार्यान्वयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

12. आय कर और निगम कर के रूप में अब बजट अनुमानों की अपेक्षा 83 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होने का अनुमान है; यह वृद्धि मुख्य रूप से तत्परता के साथ कर वसूल करने के प्रयत्नों के कारण हुई है। संघीय उत्पादन शुल्कों के अंतर्गत केवल 31 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि होगी। दूसरी ओर, सीमा-शुल्कों के अंतर्गत, बजट अनुमानों से 113 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होगा जो प्रमुख रूप से आयातों में हुई वृद्धि का बोतक है।

13. बाजार ऋणों से प्राप्त होने वाली राशि में भी बजट अनुमानों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है—इस मद में वास्तव में 294 करोड़ रुपये वसूल हुआ है जब कि पिछले मई मास में, 168 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी। राष्ट्रीयकृत बैंक निक्षेप-राशियां जुटाने के कार्य में शानदार प्रगति करते रहे हैं और जीवन बीमा निगम तथा भविष्य निधियों द्वारा भी पूर्व अनुमानों से अधिक रुपये इकट्ठा किया गया है। इस से केन्द्र को चालू वर्ष के दौरान बाजार से ऋण मिलने में बहुत सुविधा हुई। अल्प बचतों के अन्तर्गत 210 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाना चाहिए, जबकि पहले केवल 180 करोड़ रुपये की कल्पना की गई थी।

14. अनुमान है कि अब समग्र घाटा 385 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा। इस प्रकार इसमें बजट अनुमानों की तुलना में 152 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। एक सामान्य वर्ष में, घाटे में इतनी अधिक वृद्धि हो जाने से निन्ता होना स्वाभाविक था और इसलिए चालू वर्ष में ही इसका मुद्दा संबंधी प्रभाव, रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नियंत्रण की नीति के जरिये सीमित रखा गया। परन्तु सम्मानित

सदस्य यह अवश्य महसूस करेंगे कि इस विषय पर रक्षा, शरणार्थी-सहायता, बंगला देश को मदद और दैवी विपत्तियों के अतिरिक्त दायित्व के संदर्भ में विचार करना होगा। अकेले इन चार मदों पर 1888 करोड़ रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है जब कि गत मई मास में इन पर 1351 करोड़ रुपये खर्च होने की कल्पना की गई थी। शरणार्थियों के लिए बाहर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता को बाद देने के पश्चात् इन मदों में बजट अनुमानों की अपेक्षा 437 करोड़ रुपये अधिक खर्च हो जाएंगे।

### आयोजना परियोजना : 1972-73

15. महोदय, अब मैं 1972-73 की बजट व्यवस्थाओं पर आता हूँ। विकास और सामाजिक कल्याण-कार्यों की गति को बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता को वृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए 1971-72 में जो 1455 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 1972-73 में 1787 करोड़ रुपये कर दिया जाए। इस प्रकार एक ही वर्ष में 332 करोड़ रुपये यानी लगभग एक-चौथाई वृद्धि करके हम केन्द्र स्तर पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं जितना कि पिछले अनेक वर्षों में पहले कभी नहीं उठाया गया था। आयोजना-परिचय में जो वृद्धि की जा रही है वह वस्तुतः अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में फैलाई गई है। कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता के खाते में 23 करोड़ रुपये की, सिंचाई और बिजली के खाते में 18 करोड़ रुपये की, खान और धातुओं के खाते में 23 करोड़ रुपये की, पेट्रोलियम, रसायन, इस्पात और भारी इंजीनियरी सहित उद्योगों के खाते में 44 करोड़ रुपये की, नौवहन और परिवहन के खाते में 56 करोड़ रुपये की, डाक-तार के खाते में 14 करोड़ रुपये की, रेल खाते में 8 करोड़ रुपये की और परमाणु उर्जा के खाते में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

16. अब तक की सबसे अधिक वृद्धि उन योजनाओं की व्यवस्थाओं में की जा रही है जिनमें भावी विकास की संभाव्यता के साथ सामाजिक कल्याण का तत्त्व भी जुड़ा है। 1972-73 के बजट में ऐसी सब योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1971-72 के बजट में 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। एक महत्वपूर्ण नयी बात यह कि इस बार बजट में एकमुश्त 125 करोड़ रुपये की एक नई व्यवस्था की जा रही है जिससे गांवों में जलपूर्ति तथा घर बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था, गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार, प्राथमिक शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाई गई योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। चूंकि इन अत्यावश्यक सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं में बहुत अधिक अंतर है इसलिए यह महसूस किया जाता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार की एक मुश्त व्यवस्था कर देने से, प्रत्येक राज्य के उस क्षेत्र में, जहां इन कार्यक्रमों को जल्दी कार्यान्वित करना जरूरी है, हम कुछ ठोस कार्य अधिक आसानी से कर सकेंगे।

17. विभिन्न राज्यों में 6 से 11 वर्ष के अयु-वर्ग वाले बच्चों को विद्यालयों में भर्ती करने में भी बहुत सी असमानताएं हैं। विशेषतः पिछड़े इलाकों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार से क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने में सहायता मिलेगी और इससे राजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमारे 5, 60, 000 गांवों में से कोई 1, 30,000 यानी लगभग 25 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां प्रांशिक रूप से हैजे या नहरवे (गिनीवर्म) का प्रकोप रहता है। इन असुविधापूर्ण इलाकों में ग्रामीण जलपूर्ति की समस्याओं को हल करने के प्रयत्न से, ग्रामीण जनता की भलाई के कार्य में काफी सहयोग मिलेगा। गांवों में घर बनाने के लिये जमीन की व्यवस्था कर देने

से खासतौर से भूमिहीन मजदूर को मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में, मुख्यतः घने वसे हुए गाहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रमों अथवा प्राथमिक रूप से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

18. अन्य योजनाओं में, छोटे किसानों के विकास अभिकरण (एजेंसी) के लिये अगले वर्ष के बजट में 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जो इस वर्ष की 6 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था से दुगुनी है; और सीमान्तिक (मार्जिनल) किसानों और कृषि-श्रमिकों के लिये इस वर्ष की 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था को अगले वर्ष दुगुना यानी 6 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसी प्रकार, बच्चों के पोषाहार संबंधी विशेष कार्यक्रमों के लिये की जाने वाली व्यवस्था को 11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21.5 करोड़ रुपये किया जा रहा है। प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में बरानी खेती के विकास और गांवों में निर्माण कार्यक्रमों को और रोजगार उपलब्ध कराने के जोरदार कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जा रहा है और उनके लिये अगले वर्ष के बजट में कुल 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। हमें आशा है कि अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके हाल में किये गये मूल्यांकन को देखते हुए, इस समय जो व्यवस्था की जा रही है उसका आगामी वर्ष में पूरी तरह उपयोग कर लेना संभव होगा।

19. केन्द्रीय आयोजना के लिये, बजट में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक अधिष्णेय से और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अंशदान के रूप में भी साधन उपलब्ध हो सकेंगे। अनुमान है कि आयोजना के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से उपलब्ध होने वाले आंतरिक साधनों की राशि जो 1971-72 में (बजट-अनुमानों में) 233 करोड़ रुपये आंकी गई थी, 1972-73 में बढ़कर 275 करोड़ रुपये हो जाएगी। उम्मीद है कि केन्द्रीय आयोजना के लिये उपलब्ध अन्य साधन, जिनमें वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाने वाली राशि और प्रतिधारित लाभों में से रिजर्व बैंक से मिलने वाली रकम शामिल है, चालू वर्ष के 135 करोड़ रुपये के मुकाबले 1972-73 में बढ़कर 245 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार आशा है कि केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये कुल आयोजना परिव्यय, जिसमें बजट व्यवस्था तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक साधन और अन्य बजट बाह्य साधन शामिल हैं, 1971-72 के 1823 करोड़ रुपये के मुकाबले, अगले वर्ष बढ़कर 2307 करोड़ रुपये हो जाएगा, अर्थात् इसमें 484 करोड़ रुपये यानी 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

#### राज्य-प्रायोजनाएं

20. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि राज्यों की आयोजनाओं के परिव्यय में भी काफी वृद्धि होगी। योजना आयोग ने राज्य सरकारों के साथ जो विचार-विमर्श किया है उसको देखते हुए यह अनुमान है कि राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की 1972-73 के वर्ष की आयोजना का परिव्यय 1666 करोड़ रुपये होगा जब कि वह 1971-72 में 1440 करोड़ रुपये था। इसमें राज्यों को और संघीय राज्य-क्षेत्रों को केन्द्र से आयोजना सहायता के रूप में मिलने वाली 782 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। सम्मानित सदस्यों को मैं यह बतला देना चाहूंगा कि केन्द्रिय आयोजना के परिव्यय में की गयी वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग वाम्नाव में उन योजनाओं के लिये है जो स्वयं राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ और कार्यान्वित की जा रही हैं।

21. आयोजना-सहायता के अतिरिक्त, उन राज्यों को जिनके यहां आयोजना-भिन्न कार्यों के लिये साधनों की बहुत कमी है, ऋणों के रूप में विशेष सुविधा दिये जाने की योजना आगे भी चालू रखी जाएगी। इस मद के अन्तर्गत अगले वर्ष के लिये 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु यदि राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका प्रस्तावित आयोजना-परिव्यय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिये बिना पूरा हो जाये तो उनको अपने आप भी बड़े पैमाने पर साधन जुटाने होंगे। जैसा कि सदन को मालूम है, योजना मंत्री और मैं राज्यों के साथ इस संबंध में निकट संपर्क रखते रहे हैं। मुझे भली भांति मालूम है कि अल्प अवधि में पुराने ओवरड्राफ्टों को साफ करने के मामले में कुछ राज्यों के सामने वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों को मानते हुए हमने योजना आयोग से परामर्श करके यह व्यवस्था की है कि इन राज्यों को अपने वर्तमान ओवरड्राफ्ट तुरन्त साफ करने के लिये नहीं कहा जाएगा परन्तु उन्हें 1971-72 के अंत में जो अनुमानित ओवरड्राफ्ट थे उनका केवल 15 प्रतिशत भाग अगले वर्ष वापस चुका देना होगा। राज्य सरकारें इस बात के लिये सहमत हुई हैं कि वे ओवरड्राफ्ट को उत्तरोत्तर कम करने के लिये कदम उठाएंगी, और हम कुछ ऐसी नई प्रक्रियाएं अपनाने का विचार कर रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ओवरड्राफ्टों को राज्यों के व्यय की वित्त-व्यवस्था करने का एक बराबर जारी रहने वाला तरीका न बना लिया जाए।

22. इस संबंध में मैं यह भी बतला दूँ कि हम छठे वित्त आयोग के गठन और उसके विचारणीय विषयों के बारे में भी शीघ्र ही घोषणा करने वाले हैं। हमारी संघीय शासन पद्धति में, केन्द्र और राज्यों के बीच संतोषजनक वित्तीय संबंधों को विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो समस्त देश की प्रगति और समरसता को प्रभावित करता है। अब से दो वर्ष बाद चालू की जाने वाली पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये मूलाधार बनाने में अगले वित्त आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

#### अन्य व्यय और प्राप्तियाँ : 1972-73

23. आयोजना के बाहर व्यय को अधिक से अधिक सीमित रखने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है। अगले वर्ष रक्षा कार्यों के लिये 1408 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, यह राशि लगभग उतनी ही है, जितनी चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में थी। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि लागत, वेतन और मंहगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि के लिये व्यवस्था करने के अलावा, हमें युद्ध के दौरान हुई क्षतियों को पूरा करने के लिये और जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिये सर्वोच्च कोटि का बलिदान दिया है उनके परिवारों की देखभाल के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था करनी है। हमारी उत्कट अभिलाषा और प्रयास है कि निकट अतीत के कष्टों और पीड़ाओं में से इस महान उपमहाद्वीप में शान्ति और समरसता की एक नवीन भावना का उदय हो जिससे इस उपमहाद्वीप के सभी 70 करोड़ निवासी अपनी समस्त शक्तियों को भूख, अभाव, रोग और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण रूपी अपने सामान्य शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने में लगा सकें।

24. मुझे आशा है कि आय कर और निगम कर में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की 85 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, 1972-73 में 1060 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकेगी। उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व चालू वर्ष के 2103 करोड़ रुपये से बढ़कर 2330 करोड़ रुपये और सीमाशुल्कों का राजस्व 652 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो जाता

चाहिये। विशेष उद्योगों (लेवी) से, जिन्हें मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में खालू रखना बहुत जरूरी है, खालू वर्ष के 20 करोड़ रुपये की तुलना में, अगले वर्ष 70 करोड़ रुपये प्राप्त होगा।

25. दुर्भाग्य की बात है कि अतिरिक्त राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग खाद्य संबंधी राज सहायता (सब्सिडी) में वृद्धि हो जाने से प्रति संतुलित हो जाएगा, इस मद के लिये खालू वर्ष के बजट अनुमानों में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जब कि अगले वर्ष के बजट में इसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान अन्न वसूली और निर्गम मूल्यों के अनुसार, खाद्य संबंधी राज सहायता का बोझ अगले वर्ष वस्तुनः 120 करोड़ रुपये होगा। मैंने इससे कुछ कम यानी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा इरादा है कि इस बोझ को कानू में रखने के लिये समुचित उपचारात्मक उपाय करके इसे, अधिक न बढ़ने दिया जाए।

26. खाद्यान्न के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह स्वागतयोग्य है परन्तु उसने एक दूसरे तरीके से राजस्व संबंधी बोझ को बढ़ा दिया है। अनुमान है कि 1972-73 के दौरान खाद्यप्राप्तों के संकट निरोधक भंडार को ढोने के लिये भारतीय खाद्य निगम को 120 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता होगी। मैं इस कार्य के लिये बजट में केवल 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूँ, और शेष 95 करोड़ रुपये का इंतजाम निगम को बैंकों से अतिरिक्त राशि उधार लेकर करना होगा। फरवरी, 1972 के अंत में, इस निगम द्वारा बैंकों से उधार ली गई राशि 350 करोड़ रुपये के ऊंचे स्तर तक पहुँच चुकी थी। आगामी वर्ष में इन राशि में 95 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जाएगी और यदि अन्य क्षेत्रों की ओर से बैंकों को की गई मागों में तबनुसार कमी न आई तो स्वाभाविक है कि बैंकों के ग्राहकों पर भी अनुचित दबाव पड़ेगा। इसीलिये अगले वर्ष बाजार ऋणों के रूप में प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि को केवल 215 करोड़ रुपये तक ही आँका गया है। इस प्रकार, खाद्यान्नों की वसूली अब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्रीय राजस्व-कोष को और देश में आय के वितरण को भी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है।

27. अनुमान है कि अगले वर्ष यानी 1972-73 में विदेशी ऋणों के रूप में 374 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होगी जो इस वर्ष के 469 करोड़ रुपये से काफी कम है। हाल की घटनाओं ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए भी हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदेशी सहायता के बिना क्रमशः अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की हमारी नीति किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए ही है। इसका जोर हमारे अपने आंतरिक प्रयत्नों को सशक्त बनाने की ओर है। अब भी कुछ ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जैसे रुई, तेलहन, उर्वरक, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और पहले लगाए गए उपकरणों के लिए फाब्रिक पुर्जे, जहाँ हमें आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार, खनन, मछली उद्योग और विविध प्रकार की इंजीनियरी और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए अति वक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके हम अपनी निर्यात की आमदनी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। हम इन सब क्षेत्रों में तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विस्तृत आयोजनाएँ बना रहे हैं जिनसे हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएँ अनुचित रूप से आयातों पर निर्भर रहे बिना, पूरी हो सकेंगी और निर्यात बढ़ाने के लिए भी कुछ बच सकेगा। आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-प्रोत्साहन के जरिये आत्मनिर्भरता की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए वित्त की या कोई अन्य प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी।

28. कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार अगले वर्ष के बजट में कुल मिलाकर 375 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। राजस्व खाते में 219 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा परन्तु पूँजी खाते में 594 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जो उस अधिशेष से अधिक होगा।

### उपसंहार

29. संक्षेप में मैं इस समय 1972-73 का जो बजट पेश कर रहा हूँ उसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आयोजना के परिणाम में काफी वृद्धि काँ गई है। केन्द्रीय आयोजना (खास) की बजट व्यवस्था में 332 करोड़ रुपये यानी लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। आन्तरिक अधिशेषों और अन्य बजट-बाह्य साधनों को शामिल करने के बाद केन्द्रीय आयोजना में 484 करोड़ रुपये यानी 27 प्रतिशत की वृद्धि होती है। केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की आयोजनाओं का एक साथ हिसाब लगाने पर अगले वर्ष की आयोजना के लिए जैसी कि इस समय कल्पना की गई है कुल मिलाकर चालू वर्ष के 3263 करोड़ रुपये के मुकाबले 3973 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है अर्थात् इसमें 710 करोड़ रुपये यानी 22 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार आयोजना परिणाम में पर्याप्त वृद्धि कर देने से आगे आने वाले महीनों में आर्थिक विकास को भारी सहयोग मिलेगा। हमारा यह अनुभव रहा है कि सरकारी क्षेत्र के आयोजना-परिणाम में वृद्धि करना सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को फिर से बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अतः हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष आयोजना-परिणाम में की गयी वृद्धि विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति को फिर से तेज करने के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होगी, जहाँ हाल की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

30. केन्द्र की आयोजना के लिए बजट में की गई कुल व्यवस्था में से कोई 240 करोड़ रुपये की राशि, सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास पर बल देने वाली योजनाओं के लिए निर्धारित की जा रही है। मुझे यह भलीभाँति मालूम है कि यह 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इस समस्या के विशाल आकार-प्रकार की तुलना में बहुत कम है। परन्तु सम्मानित सदस्य मुझसे इस बात पर अवश्य सहमत होंगे कि यह हमारे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त वर्गों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किये जा रहे हमारे सच्चे प्रयास की द्योतक है।

31. यह कुछ संतोष का विषय है कि आयोजना-परिणाम में पर्याप्त वृद्धि करने के बावजूद और अतिरिक्त साधन-संग्रह को हिसाब में लिये बिना ही, 1972-73 के केन्द्रीय बजट का घाटा अनुमानतः 375 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा; यह संतोषजनक स्थिति मुख्य रूप से इस तथ्य का फल है कि पिछले नाजुक वर्ष के दौरान वास्तव में हम तीन भिन्न-भिन्न बजट पेश कर सके थे, जिनमें अतिरिक्त साधन जुटाने के सबल उपाय किए गए थे। गत वर्ष अपनाए गए कराधान संबंधी उपायों से एक पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

32. हालाँकि केन्द्रीय बजट हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है, तथापि उसे हमारी आर्थिक रीति-नीतियों में मूल मूल परिवर्तनों के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। गत वर्ष, सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए थे। आम बीमा के प्रबन्ध को हाथ में लेना, ऋणों को सामान्य श्रेणियों में बदलने और सहायता-प्राप्त उद्यमों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने के बारे में वित्तीय संस्थाओं की निर्देश देना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई क्षमता को उद्योग और कृषि के क्षेत्र में छोटे और नए उद्यम-कर्ताओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में लगाने का सतत प्रयत्न

करने रहना और व्याज की भिन्न-भिन्न दरों को नोति—ये सब कार्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के हमारे प्रबल अभियान के विभिन्न पहलू हैं। सम्मानित सदस्य आप्रवस्त रहें कि हम आगामी महीनों में उमी भावना के साथ और व्यापक क्षेत्र में अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे जिससे समाजवादी समाज का निर्माण करने के आदेश का तेजी और जोश के साथ पालन किया जा सकेगा।

33. महोदय, मुझे सम्मानित सदस्यों का अधिक समय न लेते हुए, अब कराधान के मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। पिछले 12 महीने में वास्तव में तीन बजट पेश कर देने के बाद मुझे यह आशा रखना स्वाभाविक हो सकता है कि मैं कम से कम एक वर्ष तक और कर न लगाऊँ। परन्तु मैं अपने आपको इस तरह की एक शिष्ट स्थिति में नहीं रखना चाहता। 375 करोड़ रुपये के घाटे को योंही बिना कोई व्यवस्था किए, छोड़ देने से मूल्य-स्थिरता को खतरा रहेगा। हमने राज्य सरकारों के लिए भी राजस्व जुटाने के सम्बन्ध में कुछ बचन दे रखे हैं। राजस्व नीति को भी आत्मनिर्भरता और समता के बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में अवश्य हाथ बंटाना चाहिए। कुछ रियायतें देने में भी मुझे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नया बजट पेश करते हुए कुछ हद तक राजस्व ढाँचे को सुव्यवस्थित करने का भी अवसर मिलता है।

34. भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में नियुक्त प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने पिछले दिसम्बर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में, काले धन को बाहर निकालने, करों के अपवचन और परिवर्जन को रोकने और करों की बकाया राशि को कम करने के लिए बहुत-से बहुमूल्य और दूरव्यापी सुझाव दिए गए हैं। इस रिपोर्ट की प्रतियां सम्मानित सदस्यों के लिए शीघ्र ही उपलब्ध कर दी जाएंगी। इस सदन में यह श्रमकर कहा जाता रहा है कि कर-पद्धति में मूलभूत परिवर्तन वार्षिक वित्त विधेयक की बजाय एक कराधान संशोधन विधेयक के जरिये किए जाएं, ताकि सम्मानित सदस्यों को, सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत रूप से विचार करने के लिए अधिक समय मिल सके। तदनुसार, मैं शीघ्रातिशीघ्र एक अलग विधान प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा समिति की उन सिफारिशों को, जो सरकार को स्वीकार्य हैं और जिनके अनुसार वर्तमान कर-विधियों में बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्रियान्वित किया जायेगा।

35. देश में कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों से बना हुआ कुटुम्ब जो उपभोग की दृष्टि से एक सामान्य इकाई माना जाता है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष कराधान के प्रयोजन से भी एक सामान्य केन्द्र बिन्दु होता है, वह प्रत्यक्ष कराधान के प्रयोजनों के लिए भी, कार्यशील प्रतिभों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं के साथ, एक अधिक समुचित और साम्यिक आधार है। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की वर्तमान कराधान प्रणाली से भी कर-परिवर्जन को प्रोत्साहन मिलता है। इन दो परस्पर सम्बन्धित प्रश्नों पर वांचू समिति के सदस्यों ने अनेक वैकल्पिक सुझाव दिए हैं। सरकार इन सुझावों पर भलीभांति विचार करेगी और आयकर अधिनियम तथा धन कर अधिनियम को आवश्यक सीमा तक नया रूप देने के लिए यथासमय एक अलग विधान प्रस्तुत करेगी।

36. इसी बीच में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रत्यक्ष कराधान के ढाँचे में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन परिवर्तनों का उद्देश्य या तो एक कठिन वर्ष में कुछ अतिरिक्त राजस्व पैदा करना है या वांचू समिति की ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करना है जिनका वर्तमान कर-विधियों में संश्लेषण से समावेश किया जा सकता है।

## प्रत्यक्ष कराधान

37. यह मानकर कि कोई समाचार न मिलना कुशलता का सूचक है, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनियों से भिन्न करदाताओं के मामले में, आयकर की दरों में तथा आयकर के अधिभाग की दरों में भी कोई परिवर्तन न किया जाए।

38. लोगों को अपने नियमित कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए किसी आकस्मिक या अल्प-कालिक अथवा काल्पनिक श्रुतियों की ओर लालायित होने से रोकने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि एक वर्ष में 1,000 रुपये से ऊपर की आकस्मिक और अनावर्ती आय के सम्बन्ध में इस समय जो छूट मिली हुई है उसे वापस ले लिया जाए। किन्तु विशेषतः वित्त मंत्री को उन लोगों पर कोई गुस्सा नहीं बिखाना चाहिए जिन पर भाग्य-देवता की विशेष कृपा होती हो। अतः राज्यों की लाटरियों और अन्य लाटरियों से मिलने वाले इनामों पर रियायती दर से कर लगाया जाएगा। लाटरी का इनाम जीतने वाले लोग भी शायद, पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने वाले उन लोगों जैसी खुशी की स्थिति में होते हैं जिनकी सम्पत्ति का मूल्य बिना प्रयत्न स्वतः बढ़ जाता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार, ऐसी जीतों से होने वाली आय का हिसाब लगते समय 5,000 रुपये और शेष राशि के 50 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति होगी। किन्तु, जिन पर भाग्य की कृपा हुई हो उन्हें भी पहले राजस्व-कोष की बेदी पर कुछ भेंट चढ़ानी चाहिए। इसलिए मैं वर्ग-पहेलियों और लाटरियों की राशि पर 34.5 प्रतिशत की दर से छोट पर कर की कटौती किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार जो आकस्मिक हानियां होंगी उनको उसी प्रकार की आय में ही प्रति-सन्तुलित कर लिया जाएगा।

39. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निगमों और कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगियों पर उनके 2 प्रतिशत की दर से छोट पर कर की कटौती करने के लिए व्यवस्था की जाए। व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से भिन्न ठेकेदारों द्वारा आगे उप-ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगियों पर, 1 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी। आशा है, राजस्व विभाग और ठेकेदारों के इस पारस्परिक सम्बन्ध से अदायगियों में सर्वत्र अधिक तत्परता आएगी।

40. पहली अप्रैल, 1972 से, सरकार ऐसी आपसी की रकम पर, जिसकी अदायगी में देर हो गई होगी, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगी। सम्मानित सदस्यों को स्मरण रहे कि इस समय हम जिस दर पर ब्याज दे रहे हैं वह केवल 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। यह उचित ही होगा कि सरकार को प्रत्यक्ष करों की अदायगी में देरी होने की सूरत में लिए जाने वाले ब्याज की दर की भी इसी प्रकार 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

41. वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए रखे जाने वाले आभूषणों के अन्तरण से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ अब तक पूंजीगत अभिलाभ-कर की परिधि में नहीं आते। इस कारण, आभूषणों के बनावटी सोदे होने हैं जिनका उद्देश्य कराधान से बच निकली आय को विनियमित करना होता है। इसलिए मैं इस त्रुटि को सुधारने का प्रस्ताव करता हूँ।

42. सहकारी समितियों से प्राप्त होने वाले लाभांश इस समय आयकर से पूर्णतः मुक्त हैं। मुझे इस छूट में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता और मैं इसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। किन्तु ये लाभांश आय की उन श्रेणियों में शामिल किए जाएंगे जिन पर एक वर्ष में 3,000 रुपये तक आयकर से छूट मिल सकती है।

43. इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 6 करोड़ रुपये और 1972-73 में 3 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा होगा।

44. निगम कराधान के विषय में, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में लगी हुई स्वदेशी कंपनियों के मामले में, लाभों के 5 प्रतिशत की जो विशेष कटौती की जाती है उसे बिलकुल हटा दिया जाए। इससे एक पूरे वर्ष में 6 करोड़ रुपये और 1972-73 में 4.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

45. कुछ महीने पहले जब हमने विशेष अधिभार (सरचार्ज) लगाया था तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने यह पूछा था कि कंपनियों के करों पर अधिभार की दर 2.5 प्रतिशत क्यों रखी गई है जबकि रेल यात्री-किराये सहित अन्य बहुत-सी मदों पर अधिभार 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। अब मैं इस भेदभाव को हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ। 1972-73 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए, अधिभार की दर, सभी कंपनियों द्वारा देय आयकर पर 2.5 प्रतिशत ही रहेगी। किन्तु 1972-73 के वित्तीय वर्ष में जो आयकर अग्रिम रूप से देय होगा, उस पर 5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। इस परिवर्तन से एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपये और 1972-73 में 9 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

46. वित्त विधेयक में और बहुत से परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य करों के अपवंचन या परिवर्जन को रोकना और बचत तथा विवेश को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को युक्ति-संगत बनाना है। उदाहरणार्थ, बांधू समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्त और धार्मिक न्यासों (ट्रस्ट) के कराधान के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। ऐसी संस्थाओं को मिलने वाले स्वैच्छिक अंशदानों पर आयकर में तभी छूट मिल सकेगी जबकि उनका उपयोग पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा। अथवा उन्हें इन प्रयोजनों के लिए निविष्ट तरीके से संचित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सम्बन्ध इन बातों से है : कर से छूट पाने के योग्य बनने के लिए न्यास का अनिवार्यतः पंजीकरण करवाना और एक चार्टर्ड लेखापाल द्वारा उसके लेखों की परीक्षा करवाना, यह निश्चय करने के लिए सम्बन्धियों की परिभाषा का विस्तार करना कि क्या न्यास की आय या सम्पत्ति का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि उसके कारण वह कर से छूट पाने का हकदार नहीं रहेगा, और यदि न्यास की आय या परिसम्पत्ति का कोई भाग न्यास के संस्थापक या न्यास के किसी बड़े अंशदाता या न्यासियों और उनके सम्बन्धियों के लाभ के लिए काम में लाया जा रहा हो तो न्यास को धन-कर का दैनंश बनाना, आदि।

47. निवेश और बचत के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में औद्योगिक स्वत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या भागीदारी फर्मों में लगाई गई पूजी को अब उन परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाएगा जिन्हें 1.5 लाख रुपये तक धन-कर से छूट मिल सकती है। जब छूट-प्राप्त परिसम्पत्तियों की एक श्रेणी को ऐसी परिसम्पत्तियों की एक दूसरी श्रेणी में बदला जाएगा तो कम से कम छः महीने तक धारण करने की आवश्यक अवधि का हिसाब दोनों परिसंपत्तियों की धारण की अवधि के संदर्भ में लगाया जाएगा। इससे वह षठिनाई दूर हो जाएगी जो संचित वित्तीय निधि अंशदानों के बहुत-से प्राप्तिकर्ताओं को महसूस होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट-बद्ध बीमा आयोजना के अंतर्गत किए गए अंशदानों को, जीवन बीमा के प्रीमियमों और भविष्य निधियों में किए गए अंशदानों की तरह ही, एक व्यक्ति की कर-योग्य आय का हिस्सा लगाते हुए, घटाया जा सकेगा।

48. अनुमोदित उपदान निधियों (ग्रेज्युइटी फंड) की आय आगे आने वाले कर-निर्धारण-वर्ष 1973-74 से आय-कर से मुक्त हो जाएगी। स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में उपदान की जो राशि आय-कर से मुक्त होगी वह सब मामलों में अधिक से अधिक पूरे सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के एक महीने के आधे वेतन या 15 महीने के वेतन अथवा 24,000 रुपये की राशियों में से जो भी सबसे कम हो उसके बराबर होगी।

49. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश में आय-करदाताओं के छोटे किन्तु प्रकार वर्ग को सरकार की ओर से कोई विशेष मान्यता मिलनी चाहिए। अतः मैं प्रत्येक करदाता को शीघ्र ही एक अलग और स्थायी खाता-संख्या देने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई पहचान चिह्न नहीं है जिसमें आसानी से पता न चल सकता हो, और यदि इस प्रकार की व्यक्तिगत खाता संख्याओं के कारण करों को टालना कठिन हो जाए तो भी मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता।

50. अंत में मैं उस मांग के बारे में कहना चाहता हूं जो उद्योग क्षेत्र द्वारा की गयी है; वह यह है कि विकास-छूट वापस लिये जाने की स्थिति में, सरकार को राजस्व संबंधी कुछ अन्य रियायतें देनी चाहिए और उनके बारे में पहले से ही घोषणा कर देनी चाहिए ताकि देश में औद्योगिक विकास को लगातार गति मिलती रहे। सरकार राजस्व संबंधी रियायतें देने के विरुद्ध नहीं है। किन्तु यह महसूस किया जाता है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व संबंधी रियायतें सामान्य अथवा सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, अपितु वे विशिष्ट रूप से हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, ऐसे प्रोत्साहन देना वांछनीय होगा जिनसे थम जैसे भरपूर परिमाण में उपलब्ध होने वाले साधनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलता हो, न कि पूजी जैसे साधनों के प्रयोग को, जिनकी अभी आगे काफी लंबे अरसे तक कमी रहेगी। वांचू समिति ने भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए अनेक सिफारिशों की हैं। इन सभी सुझावों की भली भांति जांच करने के बाद, इसी वर्ष कुछ समय बाद हम कराधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें इस संबंध में कुछ विशिष्ट उपबंध रहेंगे। इन उपबंधों का उद्देश्य, मुख्य रूप से, देश के पिछड़े इलाकों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा।

51. प्रत्यक्ष कराधान में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप पूरे एक वर्ष में 24 करोड़ रुपये की और 1972-73 में 16 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से लगभग 14 करोड़ रुपया केन्द्र के हिस्से में आएगा। मैं कर-अपवर्चन को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई परिवर्तनों के फलस्वरूप कर-संग्रह में संभावित वृद्धि को भी जमा खाते डाल सकता था। किन्तु मैंने स्वयं अभिमत रूप से इन प्राप्तियों के लिए कोई श्रेय न लेने का निश्चय किया है।

52. महोदय, अब मैं उन करों की ओर आता हूं जिन्हें शायद कोमल शब्दों में अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

### सीमा शुल्क

53. सीमा शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे पास केवल एक ही मुख्य प्रस्ताव है। यह स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में हमने अधिकांश आयात भाल पर मूल्यानुसार 2.5 प्रतिशत की दर से और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की ऊंची दर से नियामक शुल्क लगाया था। आयात पर सामान्य रूप से अंकुश लगाने की आवश्यकता अब भी उतनी ही अधिक है जितनी कि पहले

कभी थी। नियामक शुल्क लगाने समय यह सुनिश्चित कर लेना भी आवश्यक है कि आयात शुल्क दरों में जो सरलीकरण पिछले वर्ष किया गया था उसमें अनुचित रूप से गड़बड़ न हो जाए। अतः मैं जिन वस्तुओं पर 100 प्रतिशत या इससे अधिक की दर से शुल्क लगता है उन सब पर और जो चुनी हुई वस्तुएँ गत दिसम्बर में 10 प्रतिशत की सूची में शामिल की गई थीं उन पर भी मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की एक नई दर उन सभी वस्तुओं पर लगाई जायगी जिनपर 60 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से नीची दर पर शुल्क लगता है। शेष वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत की दर से नियामक शुल्क लगता रहेगा। किन्तु जो वस्तुएँ गत दिसम्बर में पूर्णतः शुल्क-मुक्त थीं वे आगे भी शुल्क-मुक्त रहेंगी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 8.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

54. जिन उपबन्धों के अन्तर्गत हम नियामक सीमा शुल्क लगा सकते हैं उन्हें आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसलिए नियामक उत्पादन-शुल्क संबंधी उपबन्धों के अनुसार आयात वस्तुओं के मूल्य के 15 प्रतिशत की दर तक नियामक सीमा शुल्क लगाने की शक्ति भी प्राप्त की जा रही है।

#### उत्पादन शुल्क

55. उत्पादन शुल्क के संबंध में, मैं उन वस्तुओं की सूची में और कोई नाम नहीं जोड़ना चाहता जिन पर ये शुल्क लगते हैं। परन्तु सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि नए क्षेत्रों और विषयों ने खोज किए बिना भी, अधिक गहन प्रयत्नों के द्वारा आमदनी को बढ़ा लेना संभव होगा; और यह एक ऐसा दायित्व है जिससे मैं बच नहीं सकता।

56. चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को आगे भी चालू रखने के निर्णय के अनुसार, हम इन अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के समग्र भार को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निकासियों (क्लीयरेंस) के मूल्य के 10.8 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वचन-बद्ध हैं।

57. इस उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनिर्मित तम्बाकू पर लगने वाले प्रभावी मूल शुल्क के 15 प्रतिशत के हिसाब से पिछले दिसम्बर में लगाए गए नियामक शुल्क से प्राप्त होने वाली सारी राशि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में बदल कर राज्यों को दे दी जाए। विभिन्न किस्मों पर लगने वाले इस अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को भी ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जा रहा है। उपर्युक्त रूप परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यों को अतिरिक्त शुल्कों के रूप में 11.56 करोड़ रुपये तक की प्राप्ति होगी जब कि केन्द्र को नियामक शुल्कों के रूप में 9.70 करोड़ रुपये की हानि हो जायगी। साथ ही, अनिर्मित तम्बाकू की विभिन्न किस्मों पर मूल और विशेष शुल्कों को एक सामान्य योजना के अनुसार जिसके बारे में मैं अभी बतलाऊंगा, एक साथ मिलाया जा रहा है। ऐसा करते हुए मैंने केन्द्र को होने वाली राजस्व-हानि को कुछ अंशों में पूरा करने के लिए विभिन्न किस्मों की दरों को बढ़ाकर पूर्णांकित कर दिया है। राज्यों के लिए लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को छोड़कर इस सम्मिलित शुल्क की प्राप्ति में 9.31 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

58. सिगरेटों के संबंध में, इसी प्रकार के युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) और पूर्णांकन से राज्य सरकारों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में 7.63 करोड़ रुपये का लाभ होगा और अन्य शुल्कों में जिन्हें अब आपस में मिला दिया जायेगा और जिनमें राज्यों का भी हिस्सा होगा, 4.64 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

59. वस्त्रों के क्षेत्र में, मैं नकली रेशम के कपड़ों से राज्यों के लिए कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, सभी शुल्कों को हिसाब में लेते हुए और प्रति वर्ग मीटर मूल्य के आधार पर नकली रेशम के कपड़ों पर चार भिन्न-भिन्न दरें, यानी 3 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दरें लागू होती हैं। मैं 5.7 प्रतिशत की दर को घटाकर 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर की जो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ऊंचे मूल्य के कपड़े पर लगती है, बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 8.59 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व में से, अतिरिक्त शुल्कों के रूप में राज्यों का हिस्सा 5.80 करोड़ रुपये होगा और शेष राशि केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित होने वाले पूल में जमा होगी।

60. संक्षेप में, अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में 25 करोड़ रुपये का अग्रिक राजस्व प्राप्त होगा, यह सारी वृद्धि की राशि राज्यों को मिलेगी। सम्मानित सदस्यों को ज्ञात रह कि मैंने इस सारी प्रक्रिया में चीनी को बिल्कुल अछूता छोड़ दिया है।

61. पाँचवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जो विशेष उत्पादन शुल्क पहले केवल केन्द्र के लाभ के लिए लगाए हैं उन्हें भी 1972-73 से विभाज्य पूल में शामिल कर लिया जाना चाहिए। इसी सिद्धान्त के अनुसार, मैंने विशेष उत्पादन शुल्कों को मूल उत्पादन शुल्कों में मिला देने का और दरों के ढाँचे में कुछ सरलता लाने के लिए सम्मिलित दरों को पूर्ण किया करने का निश्चय किया है। इसके फलस्वरूप, कुछ आधा दर्जन अपवादों के साथ, उत्पादन शुल्क की सभी मूल्यानुसार दरें 6 विभिन्न सोपानों (स्लैब) अर्थात् 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अन्तर्गत आ जाएँगी। उदाहरणार्थ, सीमेंट के मामले में, 20 प्रतिशत के मूल शुल्क और 4 प्रतिशत के विशेष शुल्क के बदले 25 प्रतिशत का एक सम्मिलित शुल्क लगेगा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर 15 प्रतिशत का मूल शुल्क और 3 प्रतिशत का विशेष शुल्क लगता है उन पर अब 20 प्रतिशत की सम्मिलित दर लागू होगी। सेटेक्स फोम स्पंज, पोल्यूरिथन फोम और इस फोम से बनी हुई वस्तुएँ, और मोटर गाड़ियों के गायर—ये केवल चार चीजें हैं जिन पर 40 प्रतिशत का मूल शुल्क और 8 प्रतिशत का विशेष शुल्क लगता है। इन वस्तुओं के लिए नई सम्मिलित दर 50 प्रतिशत होगी। यदि सम्मानित सदस्य यह समझते हों कि पूर्णांकन की विधि से सदा राजस्व कोष को ही लाभ मिलता है तो मैं उन्हें जल्दी से यह बतला दूँ कि कच्चे के मामले में, सम्मिलित दर जो, हिसाब से 102 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है, नीचे 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पूर्णीकृत की जा रही है। वनस्पतिजन्य अगन्धित (नॉनइसेन्सल) तेलों के मामले में भी, इस दर को 110.25 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घट कर 100 रुपये प्रति मैट्रिक टन किया जा रहा है।

62. वायर लैस रिसीविंग सेटों के मामले में, कुछ संघटक पुर्जों, यानी ट्रांजिस्टरों और डायोडों पर कर लगाने की वर्तमान पद्धति से बड़े पैमाने पर तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह शुल्क पुर्जों पर से हटा दिया जाय और उसके बदले वायरलैस रिसीविंग

सेटों पर लगने वाले शुल्क में इस प्रकार उपयुक्त परिवर्तन किए जाएँ जिससे कि शुल्क का भार सेट के मूल्य के साथ साथ बढ़ता जाय। 165 रुपये तक के मूल्य वाले और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित सेटों को इस समय शुल्क में जो छूट मिली हुई है वह आगे भी जारी रहेगी।

63. युक्तिकरण के उपायों का सम्मिलित फल यह होगा कि उनसे राजस्व में 10.70 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

64. कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनके विशेष शुल्क को भूल शुल्क के साथ मिलाने के अवसर का उपयोग अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए भी किया जा रहा है। रोगन और वार्निश के मामले में, अतिरिक्त राजस्व 2 करोड़ रुपये और कागज के मामले में 5 करोड़ रुपये होगा किन्तु कागज पर शुल्क की उच्चतर दरें गते और कागज की अपेक्षाकृत अधिक मंहगी किस्मों पर ही लागू होगी। अभ्यास पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के लिए हस्तेमाल में आने वाले छपाई और लिखाई के कागज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अखबारी कागज आगे भी शुल्क-मुक्त रहेगा और मिलबोर्ड और स्ट्राबोर्ड के मामले में, जहाँ छोटे निर्माता संबद्ध हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा।

65. रेयन और संश्लिष्ट रेशे और धागे के मामले में भी ऐसी ही वस्तुओं की जा रही हैं। कृत्रिम संश्लिष्ट रेशे और धागे की अधिक मंहगी किस्मों, जैसे पोलिस्टर रेशे या धागे पर उच्चतर दर में शुल्क लगेगा। किन्तु रेयन-तन्तु धागा, जो अपेक्षाकृत मस्ता होता है, अप्रभावित रहेगा। इन परिवर्तनों से 6.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

66. अब में कुछ बड़े प्रस्तावों पर आना हूँ जिनके द्वारा केन्द्र के लिए एक ऐसे तरीके से राजस्व बढ़ाने का इरादा है जिससे हमारे अधिक बड़े सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में इस्पात पिण्डों, लौह और इस्पात उत्पादों तथा टिन प्लेटों पर प्रभावी मूल उत्पादन-शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से एक नियामक शुल्क लगाया गया था जिसका उद्देश्य आयातित इस्पात और स्वदेशी इस्पात की कीमतों के बीच के काफी बड़े अन्तर को मिटाना था। इन परिवर्तनों के बाद भी आयातित इस्पात और स्वदेशी इस्पात की कीमतों के बीच काफी अन्तर है। यह आवश्यक है कि देश में इस्पात के इस्तेमाल में किफायत की जाए और इस उद्देश्य से इस्पात की कीमत इतनी रखी जाए कि अन्तराष्ट्रीय कीमतों के साथ उसकी उचित संगति बैठ जाए। इसलिए इस्पात उत्पादों के मूल शुल्क को लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और 50 प्रतिशत का नियामक शुल्क इन बढ़ी हुई मूल दरों पर लागू होगा। इस्पात उत्पादों से कुल 36.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है जिसमें से 11.80 करोड़ रुपया नियामक शुल्कों के रूप में प्राप्त होगा।

67. ऐसे ही कारणों से, एल्यूमीनियम और उसके उत्पादों पर 25 प्रतिशत की दर से लगने वाले नियामक शुल्क को मूल शुल्क से 33½ प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है। इस उपाय से 4.18 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

68 सम्मानित सदस्य जानते ही है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में हम आयात पर काफी निर्भर रहते हैं। अभी हाल में मोटर स्प्रिट पर लगने वाले शुल्क में काफी वृद्धि की गई है और इसका अच्छा असर यह हुआ है कि बढ़ती हुई मांग रुक गई है। अतः सराहना के तौर पर, मैं मोटरधारी समुदाय को इस वर्ष अछूता छोड़ देना चाहता हूँ। किन्तु पिछले वर्ष मुझसे किरोसीन के मामले में, जहाँ आयात पर हमारी निर्भरता और भी अधिक है, जो बूक हो गई थी उसे अब मुझे ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा, किरोसीन पर शुल्क की दर अपेक्षाकृत नीची होने से, अन्य उत्पादों को, विशेषतः उच्च गति वाले डीजल तेल के साथ इसकी मिलावट को प्रोत्साहन मिलता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किरोसीन ग्रामीण और गहरी दोनों क्षेत्रों में एक सामान्य उपभोग की वस्तु है। किन्तु जिन परिस्थितियों का मैंने उल्लेख किया है, उनमें किरोसीन पर कुछ अतिरिक्त कराधान टाला नहीं जा सकता। अतः मैं किरोसीन के शुल्क को 59.75 रुपये प्रति किलो लिटर या मोटे तौर पर लगभग 6 पैसे प्रति लिटर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 29.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

69 ग. मई मास के बजट में हमने सम्मिश्रित स्नेहक तेलों और ग्रीजों पर एक शुल्क लगाया था। स्नेहक तेल कुछ हद तक केवल दो तेलों को मिलाकर, उनमें और कोई उपादन जोड़े बिना ही, तैयार किए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि इन विषयों में तेलों पर कोई शुल्क न लगाया जाए। अतः मैं वर्तमान टैरिफ सबों की परिभाषा में समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। एस्फाल्ट और बिटुमन पर तथा पेट्रोलियम बैक्सों पर लगने वाले शुल्क में भी समुचित रूप से संशोधन किए जा रहे हैं जिन से 3.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

70 यह अक्सर कहा जाता है कि कृषि के क्षेत्र की आय में पिछले कई वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इसलिए उसे भी देश की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सहयोग देना चाहिए। हमने कृषि आय और धन के कराधान के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रो० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। ट्रैक्टरों पर और उर्वरकों पर शुल्क लगाकर इस क्षेत्र से भी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब मैं उर्वरकों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 12.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अब से शक्ति-चालित पंपों पर जिनका उपयोग मुख्यतः पानी खींचने के लिए किया जाता है, 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। इस उपाय से 2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

71 कुछ और भी छोटी मदें हैं, जैसे सश्लिष्ट कार्बनिक रजक और प्रकाशकीय विरजक, जिनके शुल्क की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जा रही है, जिससे 2.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। सम्मिश्रित सांद्रितों के साथ मिले हुए वातित जलों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है और इस प्रकार उससे 1.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। शुल्क के प्रयोजनों के लिए अब पिस्टनों को भी मोटर गाड़ी के पुर्जों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस उपाय से 50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

72. विशेष शुल्क को मूल शुल्क में मिला देने के फलस्वरूप हेसियन पर प्रति मेट्रिक टन 605 रुपये की दर और अन्य जट-निर्मित वस्तुओं के मामलों में जो मुख्यतः टाट (सैकिंग) से सम्बन्धित हैं, प्रति मेट्रिक टन 385 रुपये की दर लागू होगी। मैं इन दरों को पूर्णतः कित करते हुए क्रमशः 600 रुपये और 400 रुपये प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। 50 प्रतिशत के हिसाब से लगने वाली नियामक शुल्क की दर अपरिवर्तित रहेगी। इससे राजस्व कोष को 1.76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा जिसमें से 1.20 करोड़ रुपये नियामक शुल्कों के रूप में प्राप्त होंगे।

73. हमारे कताईगर और बुनकर, युग-युग से, हमारी कल्पनाओं से भी परे तरह-तरह की नित नई किस्मों के रंग, बुनावट और डिजाइन तैयार करते आये हैं, और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को एक ऐसी वस्त्र-सम्बन्धी टैरिफ तैयार करने में कठिनाई महसूस होनी रही है जिसमें हमारे वस्त्र उत्पादों के सभी सूक्ष्म अंतरों के साथ संगति बैठाई जा सके। मैं एक बार और प्रयास करके वस्त्र सम्बन्धी टैरिफ का व्यापक युक्तिकरण करना चाहता हूँ जो काफी विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हर हालत में इस युक्तिकरण का राजस्व सम्बन्धी प्रभाव कुल मिलाकर नगण्य ही होगा।

74. अन्त में, मैं उत्पादन शुल्कों में कुछ रियायतों द्वारा पूर्णिकन करना चाहता हूँ। कुछ वस्तुओं के मामले में, 50,000 रुपये तक की शुल्क-मुक्त निकासी की अनुमति है बशर्ते कि एकक से एक वर्ष में होने वाली कुल निकासी 2 लाख रुपये से अधिक न हो। कुछ अन्य मामलों में, 1 लाख रुपये तक के मूल्य की निकासियां शुल्क-मुक्त हैं। अब मैं ऐसे सभी मामलों में जहाँ आज 50,000 रुपये की निचली सीमा अनुमत है, छूट की सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ, परन्तु 2 लाख रुपये की उच्चतम सीमा अपरिवर्तित रहेगी। अपेक्षाकृत छोटे एककों को मदद देने के इरादे से किए जा रहे इस उपाय से राजस्व कोष को एक पूरे वर्ष में 1.40 करोड़ रुपये की हानि होगी।

75. साबुन बनाने में हलके तेलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट में कुछ रियायतें दी गई थीं। सामान्य रूप से वनस्पति तेलों के संबंध में, आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हलके तेलों के इस्तेमाल के न्यूनतम प्रतिशत को 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत करके, और जब तक हलके तेलों का घटाया गया न्यूनतम इस्तेमाल चालू रहे, साबुन पर लगने वाले शुल्क पर प्रति मेट्रिक टन 4 50 रुपये की दर से रिबेट लागू करके इस सम्बन्ध में अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। यह रिबेट इन तेलों के उपयोग में होने वाली वृद्धि के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के लिए प्रति टन 1 50 रुपये की दर से क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। एक ऐसी ही रियायत साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले, धान की भूसी के तेल के सम्बन्ध में दी जाएगी जो 15 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से ऊपर धान की भूसी के तेल के उपयोग के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के लिए प्रति टन 1.50 रुपये की दर से होगी।

76. बनावस्ती बनाने में धान की भूसी के तेल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्रयोग की 7 प्रतिशत सीमा को, जो पिछले वर्ष निर्धारित की गई थी, घटा कर 1 प्रतिशत किया जा रहा है और ऐसे तेल से उत्पादित बनावस्ती पर लगने वाले शुल्क पर दिए जाने वाले रिबेट की दर, बिना किसी परिवर्तन के, 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन कायम रहेगी। इसी प्रकार, बनावस्ती बनाने

में बिनीले के तेल को अधिक हस्तेमाल करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन की दर भी क्रमबद्ध आधार पर बढ़ाई जा रही है। बिनीले के तेल से उत्पादित बनावस्पती पर इस समय जो 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की सामान्य रियायत दी जा रही है उसे वापस ले लिया जाएगा और अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। किन्तु इस प्रतिशत सीमा से आगे, 20 प्रतिशत उपयोग तक प्रति मेट्रिक टन 200 रुपये, 20 से 30 प्रतिशत उपयोग तक प्रति मेट्रिक टन 250 रुपये और 30 प्रतिशत से ऊपर उपयोग के लिए प्रति मेट्रिक टन फिर 200 रुपये रिबेट मिला करेगा। इन रियायतों से लगभग 60 लाख रुपये के राजस्व की हानि होगी।

77. सम्मानित सदस्यों को यह ज्ञान कर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष मैं डाक-तार वरों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूँ। किन्तु वित्त विधेयक में, दिल्ली पर लागू होने वाली विक्रय-कर-विधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कुछ ऐसी घुटियों को दूर करना है जिनसे दिल्ली प्रशासन को प्राप्त होने वाले विक्रय-कर के राजस्व में हानि होती है।

### उपसंहार

78. सभी प्रस्तावों को एक साथ हिसाब में लेने पर, उत्पादन शुल्कों से 1972-73 में कुल 145 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा; उसमें से 97 करोड़ रुपये केन्द्र के और लगभग 48 करोड़ रुपये राज्यों के हिस्से में आएगा। इसके अलावा, लोहे, इस्पात और ऐल्यूमीनियम से सम्बन्धित उत्पादन शुल्कों को छोड़ कर अन्य उत्पादन शुल्कों में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के सम्बन्ध में लागू किए जाने वाले संतुलनकारी आयात शुल्कों से 13.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। सीमा शुल्कों में अन्य परिवर्तनों से, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केन्द्र के लिए 8.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष करों से 1972-73 में केन्द्र के लिए 14 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। अगले वर्ष, कुल मिलाकर, केन्द्र को 133 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस प्रकार, 375 करोड़ रुपये का प्रारंभिक घाटा कम होकर 242 करोड़ रुपये रह जाएगा जो मैं समझता हूँ एक काफी निरापेक्ष-स्तर है।

79. सहोदय, अंत में, मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी जो बजट प्रस्ताव पेश किए हैं उन पर, समष्टि रूप से और हमारे राष्ट्र के सामने विद्यमान चुनौती के संदर्भ में, विचार किया जायेगा। अर्थ व्यवस्था में निवेश के स्तर को वर्तमान परिस्थिति में काफी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करना विकास, विशेषतः औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं, अपितु समाज के सर्वाधिक असुविधा-प्राप्त वर्गों के कल्याण के हेतु कुछ ठोस कार्य करने के लिए भी आवश्यक है। हमें बंगला देश को भी, उसकी अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के तात्कालिक कार्य में सहायता देनी है। हम राष्ट्र की सुरक्षितता और अखंडता के रक्षण में भीड़िल नहीं दे सकते। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को भी उचित अनुपातों तक ही सीमित रखा जाए।

80. सीमाग्य की बात है कि अगले वर्ष के परिष्य में जो अपरिहार्य और वस्तुतः आवश्यक वृद्धि होगी उसका अधिकांश भाग राजस्व की सामान्य वृद्धि से पूरा किया जाएगा। हालांकि मैं अतिरिक्त कराधान को बिलकुल नहीं ढाल सका हूँ, फिर भी मुझे आशा है, सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि आयो-जनागत परिष्य में काफी वृद्धि के द्वारा विकास और सामाजिक कल्याण कार्यों को गति प्रदान करने

में भी मैंने अनुचित सावधानी नहीं रखी है। मेरे कुछ कर-प्रस्ताव आत्म-निर्भरता जैसे अन्य उद्देश्यों को भी बढ़ावा देंगे। मैंने प्रारंभ में विकास, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, पूंजी, निवेश और साधन-संग्रह की परस्पर बेने वाली प्रक्रियाओं को तेज करने के बारे में जो कुछ कहा था उसका यही मतलब था। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि समग्र रूप में ये बजट-प्रस्ताव अर्थ-व्यवस्था को, हमारे वांछित लक्ष्यों तक पहुँचने के मार्ग में एक अगली मंजिल तक ले जाएंगे।

अन्यव.द

# Budget 1972-1973

## Speech of Minister of Finance

### 16th March, 1972

Sir,

I rise to present the Revised Estimates for the current year and the Budget Estimates for 1972-73.

#### *Economic Conditions: 1971-72*

2. In many ways, the year that is now drawing to a close has been the most eventful in our recent history. It began in the wake of a clear expression of the will of our people in favour of a bold and radical programme to promote growth with social justice. This verdict has been reconfirmed decisively in the recent assembly elections. But the beginning of the year also witnessed a reign of terror and repression in East Bengal. By November 1971, some 10 million refugees had sought shelter in our midst; and we stinted no effort or resource in looking after these hapless and heroic people. Despite this massive influx and the cost of a war, which was not of our seeking, we decided not to delay or postpone in any way the equally urgent task of development and social welfare. Instead, we sought to meet the additional burdens by two supplementary instalments of fresh taxation, by greater mobilization of voluntary savings and by a renewed drive for economies in non-Plan expenditure and speedier tax collections.

3. Above all, we met the challenge by drawing on the strength of a united people; and it is possible now to look back on the events of the past year with a degree of confidence in the economic sphere as well. Despite the extraordinary stresses and strains which were compounded by natural calamities over many parts of the country, it should be possible to end the current fiscal year with our foreign exchange reserves more than intact, Government stocks of foodgrains of nearly 8 million tonnes, the general price level reasonably stable and a deficit in the Central Budget significantly lower than what one might have apprehended.

4. To some extent, the events of the past year will continue to cast their shadow over the coming months as well. Honourable Members would appreciate that we have to assist the friendly people and Government of Bangladesh in their immediate task of reconstruction and rehabilitation. To the extent that we have drawn upon the accumulated stocks in the economy and there has been unusual wear and tear of our productive assets, these will have to be made good. But above all, now that the refugees have been able to return to their homes, we have to redirect our energies increasingly to satisfy the aspirations of our own people. While the resilience and strength displayed by the Indian economy can give us confidence, there is little room for complacency.

5. Economic conditions in the recent past contain many pointers to the areas where further sustained effort is necessary. These have been dealt with at some length in the Economic Survey. The rate of growth of the economy has slackened in 1971-72. To some extent, this is understandable as the high rate of growth in the production of major cereals in earlier years cannot—and indeed need not—be continued year after year. But this trend should be counter-balanced by an increase in the growth rate of pulses, commercial crops and industry at large. This has not happened so far. Many of our basic industries, notably steel and fertilizers, are operating well below capacity. Shortage of agricultural raw materials has affected important consumer goods industries such as textiles, sugar and vegetable oils. There are encouraging signs that many capital goods industries and those producing important intermediate products have their order books full and are maintaining a satisfactory rate of growth in production. But here again, progress is by no means uniformly good. Quite apart from tackling the immediate problems of better management, greater capacity utilization, improved raw material supply and industrial relations and a general environment of more active demand, we have to expedite the creation of additional capacity in a

number of vital areas, including the generation of electricity and fertilizers and steel where better utilization of existing capacity alone will not sustain demand for long.

6. There are also other trends which we cannot overlook. While imports other than those of foodgrains, have increased rapidly, this cannot be said of exports. As a result, the trade gap is likely to widen appreciably in the current fiscal year. The various programmes for promoting social welfare which have been taken in hand over the past two years have yet to gather momentum. Again, despite some signs of improvement, the level of savings and investment in both the public and the private sectors is inadequate to sustain a satisfactory rate of growth.

7. This situation must be rapidly transformed if the objective of growth with social justice and self-reliance is to be realised soon. Nor is a reasonable degree of price stability possible without a rapid increase in the production of the basic necessities of the people. Up to a point, and indeed to a much greater extent than is commonly realised, growth, social justice, self-reliance, investment and mobilization of resources are all mutually reinforcing processes. We have, however, also to quicken the pace by appropriate changes in budgetary and other policies. It is precisely in order to bring about such a coordinated and concerted approach to our economic problems that a Cabinet Committee on Economic Policy has been recently set up.

#### *Revised Estimates: 1971-72*

8. Coming to budgetary developments during the current year, 1971-72, Honourable Members would recall that the provision of Rs. 60 crores for refugee relief made in the Budget last May had to be increased subsequently on two occasions making a total of Rs. 360 crores for the year as a whole. Against this provision, actual expenditure is now estimated at Rs. 325 crores. At this stage, it is difficult to render any precise account of the aid pledged from abroad which will ultimately compensate us for the expenditure we ourselves have incurred. A significant part of the refugee assistance received earlier or in the pipeline is already being diverted to Bangladesh. But on a rough basis, the budgetary outlay of Rs. 325 crores may be offset to the extent of Rs. 120 crores by assistance received from abroad.

9. We have already made a sizeable beginning with assistance to the Bangladesh Government in the current year itself. Inclusive of a cash payment of about Rs. 20 crores which is being charged to the rehabilitation Budget, the commitments so far made for assistance to Bangladesh amount to roughly Rs. 130 crores. It is our intention to provide for a total commitment in this regard of Rs. 200 crores of which Rs. 82 crores might be disbursed during 1971-72 and the balance during 1972-73.

10. Defence expenditure for 1971-72 is now estimated at Rs. 1411 crores as against the Budget provision of Rs. 1241 crores, i.e., an increase of Rs. 170 crores. The expenditure on natural calamities relief at Rs. 90 crores would also be higher than the Budget Estimate of Rs. 50 crores.

11. The actual trend in expenditure on Plan schemes during the current year is a mixed one and some shortfall in Plan expenditure cannot be ruled out. But there is reason to believe that the shortfall would not be as great as in the first two years of the Plan. The implementation of important projects in the steel, fertilizer, petrochemicals and atomic energy field has picked up momentum. This is also true of the programmes with an accent on social welfare which were started in the 1970-71 Budget. But the two major programmes for employment in the rural areas and for the educated unemployed which were introduced in the last Budget could not be given proper shape for some time; and actual expenditure is likely to fall short of the Budget provision of Rs. 75 crores. Once again, our experience in the current year highlights the fact that the momentum of progress cannot be kept up merely by provision of finance. Timely preparation and selection of projects and speedy implementation are equally important.

12. Receipts under Income and Corporation tax are now estimated at Rs. 83 crores more than the Budget Estimate reflecting in the main the efforts made towards speedier tax collection. Union Excise duties will show only a moderate increase of Rs. 31 crores. On the other hand, Customs revenue will exceed Budget estimate by Rs. 118 crores reflecting primarily the spurt in imports.

13. Receipts from market loans also show a substantial increase over the Budget Estimates—the actual realisation being Rs. 294 crores against the expectation of Rs. 168 crores last May. The nationalised banks have continued to make excellent progress in deposit mobilization; and the Life Insurance Corporation and the Provident Funds have also been able to mobilise more funds than was expected earlier. This has greatly facilitated market borrowing by the Centre in the current year. Collections under small savings should amount to Rs. 210 crores against Rs. 180 crores assumed earlier.

14. The overall deficit is now expected to be restricted to Rs. 385 crores. This represents an increase of Rs. 152 crores over the Budget Estimate. An increase in deficit of this order cannot be contemplated with equanimity in a normal year; and its monetary impact even in the current year was held in check by the policy of restraint followed by the Reserve Bank. But Honourable Members would, I am sure, appreciate that it has to be judged against the additional liability on account of defence, refugee relief, assistance to Bangladesh and natural calamities. Expenditure on these four items alone is now expected to be Rs. 1888 crores as against Rs. 1351 crores envisaged last May. Even allowing for additional external assistance for refugee relief, this represents an increase of Rs. 437 crores over the Budget Estimates.

#### *Plan Outlay—1972-73*

15. Sir, I come now to the Budget provisions for 1972-73. In keeping with the imperative need to accelerate the pace of growth and social welfare, I propose to increase the budgetary provision for the Central and centrally-sponsored Plan schemes from Rs. 1455 crores in 1971-72 to Rs. 1787 crores in 1972-73. This increase of Rs. 332 crores or by nearly one-fourth in a single year represents the sharpest step-up that we have attempted in the Central sphere over the past so many years. The increase in Plan outlay is spread over virtually all the sectors of the economy. Agriculture, Community Development and Cooperation account for an increase of Rs. 23 crores; Irrigation and Power, Rs. 18 crores; Mines and Metals, Rs. 23 crores; Industry including Petroleum, Chemicals, Steel and Heavy Engineering, Rs. 44 crores; Shipping and Transport, Rs. 56 crores; Posts and Telegraphs, Rs. 14 crores; Railways, Rs. 8 crores and Atomic Energy, Rs. 30 crores.

16. By far the largest increase is being made in the provisions for those schemes which combine an element of social welfare with future growth potential. Taking all such schemes together, the Budget provision in 1972-73 would be Rs. 240 crores as compared to Rs. 130 crores in 1971-72. An important innovation relates to a new lump-sum provision of Rs. 125 crores to cover the requirements of rural water supply, rural home sites, slum clearance and improvement, primary education and schemes for the educated unemployed. Since there are wide differences in the requirements of different States for these essential amenities, it is felt that a lump-sum provision of the nature would make it easier for us to make an impact in each State in the field where such impact is most urgently needed.

17. There are large disparities among the States in terms of enrolment of children in schools in the age group 6-11. Expansion of primary education facilities, particularly in the backward areas, will help correct regional imbalance and will also provide scope for larger employment. Of our 560,000 villages, some 130,000—or almost 25 per cent—are cholera-endemic and guinea-worm infected areas. By tackling the problems of rural water supply in these disadvantaged areas, it should be possible to contribute substantially to the well-being of the rural people. The provision for rural home sites should help particularly landless labour. In some States the need would be to concentrate mainly on slum clearance and improvement in congested urban areas or on schemes designed primarily to provide employment to the educated.

18. Among other schemes, the budgetary provision for the small farmers development agency is being doubled from Rs. 6 crores this year to Rs. 12 crores next year and for marginal farmers and agricultural labourers from Rs. 3 crores to Rs. 6 crores. Similarly, the provision for special nutritional programmes for children is being increased from Rs. 11 crores to Rs. 21.5 crores. Programmes for dry farming development, rural works in drought-prone areas and the crash programme for rural employment are being continued with a total provision next year of Rs. 72 crores. It is our

hope that in the light of the experience already gained and the assessments recently made in consultation with the State Governments, it would be possible next year to utilise in full the provision that is now being made.

19. In addition to the provision made in the Budget, resources are also available for the Central Plan from the internal surpluses of public sector enterprises and by way of contribution from financial institutions. The internal resources of public sector enterprises which would be available for the Plan are expected to increase from Rs. 233 crores in 1971-72 (Budget Estimates) to Rs. 275 crores in 1972-73. Other resources available for the Central Plan including borrowings from financial institutions and contributions by the Reserve Bank from retained profits etc. are expected to increase from Rs. 135 crores in the current year to Rs. 245 crores in 1972-73. Inclusive of Budgetary provision as well as internal resources of public enterprises and other extra-budgetary resources, the total Plan outlay on Central Plan schemes is thus expected to increase from Rs. 1823 crores in 1971-72 to Rs. 2307 crores, i.e., by Rs. 484 crores or by about 27 per cent.

#### State Plans

20. I am happy to say that there will also be a substantial step-up in the Plan outlays of the States. In the light of the discussions that the Planning Commission has already had with the State Governments, the annual Plan outlay of the States and Union Territories for 1972-73 is expected to be Rs. 1666 crores as compared to Rs. 1440 crores in 1971-72. This includes a provision of Rs. 782 crores by way of Plan assistance from the Centre to the States and Union Territories. Honourable Members would also note that a substantial part of the increase in the Central Plan outlay is really on schemes which are initiated and executed by the State Governments themselves.

21. In addition to Plan assistance, the scheme of special accommodation by way of loans to those States which have substantial non-Plan gaps will be continued: the provision under this head for next year is Rs. 130 crores. But the State Governments on their own will also have to mobilize resources on a substantial scale if the Plan outlays now proposed for them are to be implemented without recourse to overdrafts from the Reserve Bank. As the house is aware, the Minister of Planning and I have been in close touch with the States in this regard. I am well aware that there are genuine difficulties in some States in liquidating past overdrafts over a short period. In recognition of these difficulties we have arranged, in consultation with the Planning Commission, that such States would not be called upon to liquidate their existing overdrafts immediately but would be asked to repay next year only 15 per cent of the estimated overdrafts at the end of 1971-72. The State Governments have agreed to take steps to reduce the overdrafts progressively, and we propose to adopt a new set of procedures to ensure that overdrafts are not used in future as a continuing mode of financing State expenditures.

22. I may also mention in this connection that we propose to announce soon the composition and terms of the Sixth Finance Commission. In our federal system, the evolution of satisfactory financial relations between the Centre and the States has a vital bearing on progress and harmony in the country at large; and the next Finance Commission will have a very important role to play in laying the base for the Fifth Year Plan which will be launched two years from now.

#### *Other Expenditure and Receipts: 1972-73*

23. Outside the Plan, every effort is being made to restrict expenditure to the minimum. The provision for defence next year is being kept at Rs. 1408 crores, i.e., about the same as the Revised Estimates for the current year. Honourable Members, I am sure, would appreciate that apart from providing for normal increases in costs, salaries and dearness allowance, we have also to make adequate provision for recouping the losses suffered during the war and for looking after the families of those who have made the supreme sacrifice for the defence of the motherland. It is our earnest hope and endeavour that out of the anguish and agony of the recent past will emerge a new spirit of peace and harmony in this great sub-continent so that all its 700 million inhabitants can devote their entire energies against their common enemies of hunger, want, disease and exploitation of man by man.

24. I expect the yield from income tax and corporation tax to increase from Rs. 985 crores (Revised Estimates) in the current year to Rs. 1060 crores in 1972-73. Revenues from Excise duties should increase from Rs. 2102 crores to Rs. 2330 crores and from Customs duties from Rs. 652 crores to Rs. 700 crores. The continuance of special levies which, I am afraid, is unavoidable in the present circumstances, would bring in Rs. 70 crores next year as against Rs. 20 crores in the current year.

25. Unfortunately, a significant part of the additional revenues will be offset by an increase in food subsidy from Rs. 30 crores in the Budget Estimates for the current year to Rs. 100 crores in the Budget Estimates next year. On the basis of present procurement and issue prices, the burden of food subsidy next year would amount in fact to Rs. 120 crores. I have made a somewhat lower provision of Rs. 100 crores as it is our intention not to let this burden grow without appropriate remedial measures to keep it in check.

26. The welcome increase in foodgrain production has added to the fiscal burden in another way. During 1972-73, the additional financial requirements of the Food Corporation of India for carrying the buffer-stock of foodgrains are estimated at Rs. 120 crores. I am making a budgetary provision in this regard of Rs. 25 crores only so that the balance of Rs. 95 crores will have to be found by the Corporation by additional borrowing from the banking system. At the end of February 1972, the Corporation's borrowing from the banking system had already reached the high level of Rs. 350 crores. A further addition of Rs. 95 crores during the coming year will naturally strain the resources of the banking system unduly unless the demands on it from other sectors are correspondingly moderated. That is why net receipts from market loans next year are assumed at the level of Rs. 215 crores only. Thus, directly or indirectly, the procurement of foodgrains is now having a substantial repercussion on the Central Exchequer as also on the distribution of income within the country.

27. Net receipts from external loans next year are also expected to show a substantial decline from Rs. 469 crores this year to Rs. 374 crores in 1972-73. Recent events have once again served as a reminder that even as we strive for greater growth and social welfare, we cannot neglect the urgent need for reducing the dependence on external assistance. Our policy to be progressively independent of external assistance is not directed at anyone other than ourselves. Its thrust is towards invigorating our own internal efforts. There are a few major areas, such as cotton, oil-seeds, fertilizers, steel, petroleum products and spare parts for equipment installed in the past where our dependence on imports is still high. Similarly, our export earnings can be increased rapidly by creating additional facilities for mining, fishing and manufacture of a large variety of engineering and consumer goods. We are making detailed plans in each of these sectors to increase production rapidly so that our growing requirements can be met without undue dependence on imports and surpluses created for augmenting exports. No effort whether by way of provision of finance or otherwise will be spared to accelerate this process of self-reliance through import substitution and export promotion.

28. At existing rates of taxation, the overall budgetary deficit next year will be Rs. 375 crores. There will be a surplus on revenue account of Rs. 219 crores, but this would be more than offset by the deficit on capital account of Rs. 594 crores.

#### *In Sum*

29. To sum up, the main feature of the Budget for 1972-73 which I am now presenting is the substantial increase in the outlay on the Plan. The budgetary provision for the Central Plan proper is being increased by Rs. 332 crores, or nearly 23 per cent. Inclusive of internal surplus and other extra-budgetary resources, the increase in the Central Plan works out to Rs. 484 crores, or 27 per cent. Taking the Centre, the States and the Union Territories together, the total provision for the Plan for the next year, as now envisaged, comes to Rs. 3973 crores as against Rs. 3263 crores in the current year, i.e., an increase of Rs. 710 crores, or 22 per cent. A substantial increase in Plan outlay of this order would be a major factor contributing to economic growth over the coming months. It has been our experience that an increase in Plan outlay in the public sector is a prerequisite for revival of industrial production whether in the public or in the private sector. It is our expectation, therefore, that the increase in Plan outlay next year will serve as a catalyst for the revival of growth particularly in the industrial sector where recent trends leave much to be desired.

30. Within the total Budget provision for the Plan at the Centre, as much as Rs. 240 crores is being earmarked for schemes with an accent on social justice as well as economic growth. I am well aware that even this provision of Rs. 240 crores is modest as compared to the magnitude of the problem. But I am sure, Honourable Members would agree that it represents a sincere effort towards meeting the basic minimum needs of the most disadvantaged sections of our society.

31. It is a matter of some satisfaction that despite the substantial increase in Plan outlay and without any credit for mobilization of additional resources, the overall deficit in the Central Budget for 1972-73 is now expected to be limited to Rs. 375 crores. This satisfactory outcome is the result mainly of the fact that during the past critical year, we were able to introduce what amounts virtually to three different budgets with substantial measures for additional resource mobilization. The total receipts on account of the taxation measures introduced last year will be of the order of Rs. 500 crores in a full year.

32. Important as the Central Budget is as an instrument for furthering our social and economic objectives, it has to be supplemented by basic changes in our economic institutions and policies. During the last year, Government has taken a number of steps in this direction. The taking over of the management of general insurance, the guidelines given to financial institutions in regard to convertibility of loans into equity and participation in the management of the enterprises assisted by them, continued effort to direct the new vitality of the nationalised banking system towards improvement in the economic conditions of the small and new entrepreneurs in industry and agriculture and the policy of differential interest rates—these are all various facets of the same thrust forward towards the goal of economic progress with social justice. Honourable Members may rest assured that we shall continue our efforts in the same spirit and over a broad front over the coming months so that the mandate for creating a socialist society is carried out with speed and vigour.

33. Sir, without taxing the patience of Honourable Members any further, I should proceed now to the business of taxation proper. Having introduced virtually three budgets in the past 12 months, I might well be expected to declare a holiday from further taxation for at least one year. But I am afraid I cannot allow myself such unique distinction. A deficit of Rs. 375 crores cannot be left wholly uncovered without danger to price stability. We have also certain commitments to the State Governments to raise revenue on their behalf. Fiscal policy must serve the larger objectives of self-reliance and equity. Nor should I fight shy of making a few concessions. The introduction of a new Budget is also an opportunity for a certain amount of spring cleaning.

34. The Direct Taxes Enquiry Committee under the chairmanship of Shri K. N. Wanchoo, ex-Chief Justice of India, submitted their Report last December. It contains a number of valuable and far-reaching suggestions for unearthing black-money, preventing evasion and avoidance of taxes and reducing tax arrears. Copies of the Report will soon be made available to Honourable Members. It has often been said in this House that basic changes in the tax system should be introduced by means of a Taxation Amendment Bill rather than through the annual Finance Bill so as to give Honourable Members more time for a detailed consideration in the light of discussion both within and outside the House. Accordingly, I propose to bring forth a separate legislation as early as possible to give effect to those recommendations of the Committee which are acceptable to the Government and which require a major change in the present tax laws.

35. There has been a feeling for some time in the country that a family consisting of husband, wife and minor children which constitutes a common unit of consumption and as such a common focal point for the incidence of indirect taxation, is also a more appropriate and equitable basis for purposes of direct taxation subject to certain safeguards for wives at work. The present tax treatment of Hindu undivided families has also encouraged tax avoidance. On these two related questions, the members of the Wanchoo Committee have made several alternative suggestions. Government will examine these suggestions carefully and sponsor separate legislation in due course for restructuring the Income Tax Act and the Wealth Tax Act to the extent necessary.

36. In the meanwhile, I propose to introduce through the Finance Bill a few changes in the Direct Tax structure which are designed either to produce some additional revenue in a difficult year or to give effect to such recommendations of the Wanchoo Committee as can be easily incorporated in the present tax laws.

#### *Direct Taxation*

37. On the assumption that no news is good news, I propose to make no change in the rates of income tax as also of surcharge on income tax in the case of taxpayers other than companies.

38. In order to remove any temptation that people may feel for neglecting their regular duties in favour of any casual or ephemeral or even imaginary pastime, I propose to withdraw the present exemption in respect of casual and non-recurring income when it exceeds Rs. 1000 in a year. However, a Finance Minister in particular should not frown upon those who are specially favoured by the goddess of good luck. Accordingly, winnings from States or other lotteries will be taxed on a concessional basis. Those who win a prize in a lottery are perhaps in the same happy position as people who enjoy a capital gain when their property appreciates in value without any effort on their part. On this principle, in computing incomes from such winnings, a deduction of Rs. 5,000 plus 50 per cent of the balance will be allowed. However, even those who are favoured by Fortune should make their offering first at the altar of the Exchequer. I propose, therefore, to provide for deduction of tax at source at the rate of 34.3 per cent from crossword puzzles and lotteries. Casual losses will be allowed to be set off only against the same type of income.

39. I propose to provide for deduction of tax at source at the rate of 2 per cent of the payments made to contractors by the Government, local authorities, statutory corporations and companies. Payments made in turn by contractors, other than individuals and Hindu university families, to sub-contractors will attract a deduction at the rate of 1 per cent. I hope this alliance between the revenue department and contractors will lead to prompter payments all round.

40. With effect from 1st April, 1972 Government will pay a rate of interest of 12 per cent per annum on the amount of refund the payment of which is delayed. Honourable Members will recall that at present the rate of interest we pay is only 9 per cent per annum. It is only fair that the interest charged when there is delay in the payment of direct taxes to the Government is also similarly increased from 9 per cent to 12 per cent per annum.

41. Capital gains arising from the transfer of jewellery held for personal use are not so far chargeable to the capital gains tax. This has given rise to fictitious transactions in jewellery in order to regularise incomes which have escaped taxation. I propose, therefore, to repair this omission.

42. Dividends received from cooperative societies are at present completely exempt from income taxation. I see no justification for this exemption and propose to withdraw it. Such dividends, however, will be included in the categories of income which qualify for exemption from income tax upto Rs. 3,000 in a year.

43. These measures are likely to yield Rs. 6 crores in a full year and Rs. 3 crores in 1972-73 of which some Rs. 2 crores will be the share of the States.

44. Coming to corporate taxation, I propose to do away altogether with the special deduction of 5 per cent of profits in the case of domestic companies engaged in priority industries. This will yield Rs. 6 crores in a full year and Rs. 4.5 crores in 1972-73.

45. Some months ago when we levied special surcharges, many Honourable Members had asked why the surcharge on company taxation was fixed at 2½ per cent when a surcharge of 5 per cent was levied on many other items including railway passenger fares. I propose now to remove this discrimination. For the assessment year 1972-73, the surcharge will continue to be 2½ per cent of the income tax payable by all companies. However, on income tax payable in advance during the financial year 1972-73, the surcharge would be at the rate of 5 per cent. This change will yield Rs. 12 crores over a full year and Rs. 9 crores in 1972-73.

46. There are a number of other changes that are proposed in the Finance Bill for preventing evasion or avoidance of taxes and for rationalising the incentives available for promoting saving and investment. A few changes are proposed, for example, in relation to taxation of charitable and religious trusts in the light of recommendations made by the Wanchoo Committee. Voluntary contributions received by such institutions will qualify for exemption from income tax only if these are applied to charitable or religious purposes or are accumulated for such purposes in the specified manner. The other important changes relate to audit by a Chartered Accountant and compulsory registration for a trust to qualify for tax exemption, extension of the definition of relatives for judging whether the income or property of the trust is being used in a manner which would constitute disqualification from tax exemption and making the trust liable to pay wealth tax when any part of the corpus or income of the trust is used for the benefit of the author of the trust, a substantial contributor to the trust or the trustees and their relatives, etc.

47. Regarding incentives for investment and saving, investment in industrial proprietary concerns or partnership firms will now be included among assets which qualify for exemption from wealth tax upto Rs. 1½ lakhs. When one category of exempt assets is changed to another category of such assets, the requirement of minimum holding for a period of six months will be reckoned with reference to the period of holding of both the assets. This would remove the difficulty that has been experienced by many recipients of accumulated Provident Fund contributions. Contributions made towards the unit-linked-insurance plan of the Unit Trust of India will qualify for deduction in computing the taxable income of an individual in the same manner as life insurance premia and contributions to Provident Funds.

48. The income of approved Gratuity Funds will be exempted from income tax prospectively from the assessment year 1973-74. The amount of gratuity that will be exempt from income tax in the case of employees other than Government employees and employees of local authorities will be subject to a uniform ceiling of half month's salary for each year of completed service or 15 month's salary or Rs. 24,000—whichever is the least.

49. I have come to the conclusion that the small but select class of income-tax payers in the country deserves some special recognition from the Government. Accordingly, I propose soon to award to each assessee a distinct and permanent account number of his own. I am afraid, there is no mark of distinction which does not lead to easy detection; and I cannot help it if individual account numbers make it difficult to avoid taxes.

50. Finally, I come to the demand which has been made by industry that while the development rebate may be withdrawn, Government should introduce some other fiscal concessions and announce them in advance so as to impart a continuing momentum to industrial growth in the country. Government is not averse to the grant of fiscal concessions. It is, however, felt that fiscal concessions for promoting industrialisation should not be general or across-the-board in character but should relate specifically to our social and economic objectives. Again, as far as possible, it would be desirable to provide incentives which encourage the use of those resources, such as labour, which are in abundant supply rather than of resources, such as capital, which will continue to be scarce for a long time to come. The Wanchoo Committee has made a number of recommendations with different objectives in view. After examining all these suggestions carefully, we propose to come up with specific provisions in the Taxation Amendment Bill which is proposed to be introduced later in the year. These provisions would be designed primarily to promote industrialisation in the backward regions of the country.

51. The total yield of all the changes in direct taxation will be Rs. 24 crores in a full year and Rs. 16 crores in 1972-73 of which the share of the Centre would be approximately Rs. 14 crores. I could also have taken credit for improvement in tax-collections as a result of the many changes designed to reduce tax evasion. But I have decided not to credit myself with any such gains in advance.

52. Sir may I now turn to what are perhaps euphemistically called indirect taxes?

### Customs Duties

53. I have only one main proposal in regard to customs duties. It will be recalled that in December last, we had imposed a regulatory duty at the rate of 2.5 per cent ad valorem on most imported products and a higher duty of 10 per cent on a few selected items. The need to exercise a general restraint on imports remains as great as ever. It is also necessary in imposing regulatory duties to ensure that the simplification of the import tariff which was introduced last year is not unduly disturbed. Accordingly, I propose to apply the 10 per cent ad valorem rate to all items which pay a duty of 100 per cent or more as well as to the few selected items which were included in the 10 per cent list last December. A new rate of 5 per cent ad valorem will apply to all items on which a duty of 60 per cent or more but less than 100 per cent is payable. The remaining items will continue to bear the regulatory duty of 2.5 per cent. However, those items which were totally exempted last December will continue to remain so. These changes will result in an additional revenue of Rs. 8.60 crores in a full year.

54. I also propose to continue the provisions which enable us to levy a regulatory duty of customs. However, in keeping with the provisions relating to regulatory duty of excise, power is being taken to levy regulatory duty of customs also upto a rate of 15 per cent of the value of the imports.

### Excise Duties

55. Coming now to Excise Duties, I propose to make no addition to the list of commodities which can be subject to such duties. But Honourable Members would appreciate that even without exploring fresh fields or pastures new, it is possible to increase the yield by more intensive cultivation; and this is a responsibility which I cannot escape.

56. Pursuant to the decision to continue the scheme of levying additional excise duties in lieu of sales-tax on sugar, textiles and tobacco, we are committed to raise the overall incidence of these additional excise duties to 10.8 per cent of the value of clearances by the end of the Fourth Plan period.

57. To this end, I propose to transfer to the States the entire proceeds of the regulatory duty of 15 per cent of the effective basic duty on unmanufactured tobacco which was levied last December by converting it into an additional excise duty which is itself being rounded upwards on different varieties. As a result, the States will gain to the extent of Rs. 11.56 crores by way of additional duties whereas the Centre will lose Rs. 9.70 crores by way of regulatory duty. At the same time, the basic and special duties on different varieties of unmanufactured tobacco are being merged in keeping with a general scheme to which I would soon refer. In the process, I have also taken the opportunity of rounding upwards the rates on different varieties to make up, in part, for the loss of revenue to the Centre. The yield of the combined duty, exclusive of the additional duties for the States, will go up by Rs. 9.31 crores.

58. In the case of cigarettes, a similar rationalisation and rounding off would result in a gain of Rs. 7.63 crores to the State Governments by way of additional excise duties and a loss of revenue of Rs. 4.64 crores under other duties which would now be combined and shared with the States.

59. In the field of textiles, I propose to raise some additional revenue for the States from art silk fabrics. At present, taking all the duties into account and depending on the price per square metre, there are four different rates that apply to art silk fabrics, namely, 3 per cent, 5.7 per cent, 8 per cent and 10 per cent. I propose to reduce the 5.7 per cent rate to 5 per cent and increase the rate of 10 per cent which applies to fabrics worth more than Rs. 5 per square metre to 15 per cent. Of the additional revenue of Rs. 8.59 crores, the share of the States by way of additional duties will be Rs. 5.80 crores and the rest will accrue to the shareable pool between the Centre and the States.

60. In short, the revenue by way of additional excise duties will increase by Rs. 25 crores and this entire increase will go to the States. Honourable Members would note that I have left sugar entirely untouched in this exercise.

61. The Fifth Finance Commission had recommended that from 1972-73, the special excise duties which have been levied in the past exclusively for the benefit of the Centre should also be included in the divisible pool. In keeping with this principle, I have decided to merge the special excise duties with basic excise duties and to round off the combined rates so as to introduce a certain measure of simplicity in the rate structure. As a result, with just half a dozen exceptions, all the ad valorem rates of excise duties will fall under 6 different slabs, namely, 10 per cent, 15 per cent, 20 per cent, 25 per cent, 30 per cent and 50 per cent. To mention a few examples, in the case of cement, the basic duty of 20 per cent and the special duty of 4 per cent will now be replaced by a combined duty of 25 per cent. Similarly, items which carry a basic duty of 15 per cent and a special duty of 3 per cent will now have a rate of 20 per cent applied to them. There are only four items, viz., latex foam sponge, polyurethane foam, and articles made from that foam, and tyres for motor vehicles where there is a basic duty of 40 per cent and a special duty of 8 per cent. The new combined rate for these items will be 50 per cent. In case Honourable Members feel that the laws of rounding off always favour the Exchequer, I hasten to inform them that in the case of coffee, the aggregate rate which works out to Rs. 102 per quintal would be rounded downwards to Rs. 100 per quintal. In the case of vegetable non-essential oils also, the rate is being reduced from Rs. 110.25 per metric tonne to Rs. 100 per metric tonne.

62. In the case of wireless receiving sets, the present system of taxing certain component parts, i.e., transistors and diodes, has given an impetus to large-scale smuggling. I propose, therefore, to remove the duty on such parts and replace it by suitable changes in the duty on wireless receiving sets in such a way that the incidence of duty will increase with the price of the set. The present exemption from duty for sets of a value not exceeding Rs. 165 and manufactured by the small-scale sector is being continued.

63. The combined result of the rationalisation measures would be a gain in revenue of Rs. 10.70 crores.

64. There are a few items where the opportunity of merging the special duty with basic duty is also being taken to raise additional revenue. In the case of paints and varnishes, the additional revenue will be Rs. 2 crores and in the case of paper, it will be Rs. 3 crores. The higher rates of duty on paper, however, will apply only to the more expensive varieties of paper and board. Printing and writing paper used for exercise note-books and text books will not be affected. Newsprint would also continue to be exempt from duty and there would be no change either in the case of mill-board and straw-board where the smaller manufacturer is involved.

65. Similar increases are being made in the case of rayon and synthetic fibres and yarn. The more expensive varieties of artificial synthetic fibres and yarn such as polyester fibre and yarn will bear higher duties. However, rayon filament yarn which is a comparatively cheap item will remain unaffected. The additional revenue from these changes is expected to be Rs. 6.50 crores.

66. I now come to a few major proposals which are intended to raise revenue for the Centre in a manner which serves at the same time some of our larger social or economic objectives. It will be recalled that last December a regulatory duty at 50 per cent of the effective basic excise duty was imposed on steel ingots, iron and steel products and tin plates so as to bridge the substantial gap between the prices of imported and indigenous steel. Even after these changes, a considerable gap remains between imported steel and indigenous steel prices. It is necessary to economise on the use of steel in the country by charging for it a price which bears a reasonable relationship with international prices. The basic duty on steel products, therefore, is being raised by about 30 per cent and the regulatory duty of 50 per cent will apply to these higher basic rates. The total additional revenue from steel products is expected to be Rs. 36.20 crores of which Rs. 11.80 crores would be by way of regulatory duties.

67. For similar reasons, the regulatory duty of 25 per cent on aluminium and its products is being raised to 33-1/3 per cent of the basic duty. This measure will yield Rs. 4.18 crores.

68. Honourable Members are also aware of our substantial dependence on imports in regard to petroleum products. The duty on motor spirit has been raised substantially in the recent past and this has had the salutary effect of curbing the growth of demand. As a token of appreciation, I propose, therefore, to leave the motoring community untouched this year. I am afraid, I have, however, to make up for the omission last year in the case of kerosene where our reliance on imports is even greater. In addition, the comparatively low rate of duty on kerosene encourages its adulteration with other products particularly with high speed diesel oil. I am well aware that kerosene is an item of common consumption both in the rural and the urban areas. But in view of the circumstances I have mentioned, some additional taxation of kerosene could not be avoided. I propose, therefore, to increase the duty on kerosene by Rs. 59.75 per kilo litre or roughly by about 6 paise per litre. This will result in an additional revenue of Rs. 29.80 crores in a full year.

69. In the Budget last May, we had introduced a duty on compounded lubricating oils and greases. Lubricating oils are also manufactured and marketed to some extent by a mere blending of two oils without any added ingredient. There is no reason why these marketable oils should not be made liable to duty. I propose, therefore, to amend suitably the definition of the existing tariff item which will yield an additional revenue of Rs. 5 crores. The duties on asphalt and bitumen as also on petroleum waxes are also being suitably revised to yield an additional revenue of Rs. 3.30 crores.

70. It has often been said that the agricultural sector which has been witnessing significant growth in income over recent years should also make an appropriate contribution to the overall needs of the country. We have appointed a Committee under the Chairmanship of Professor K. N. Raj to examine the whole question of taxation of agricultural incomes and wealth. Steps have also been taken to raise additional revenue from this sector by levying a duty on tractors and on fertilizers. I propose now to raise the duty on fertilizers from 10 per cent to 15 per cent. This will result in additional revenue of Rs. 12.50 crores. Duty at the rate of 10 per cent will also now be levied on power-driven pumps which are designed primarily for handling water. This measure is expected to yield a revenue of Rs. 2 crores.

71. There are a few other minor items such as synthetic organic dyestuffs and optical bleaching agents where the rate of duty is being changed from 15 per cent to 20 per cent with an additional yield of Rs. 2.63 crores. The duty on aerated waters with blended concentrates is being increased from 10 per cent to 20 per cent with an additional yield of Rs. 1.65 crores. Pistons will not be added to the list of motor-vehicle parts for the purposes of duty. The revenue yield from this would be Rs. 50 lakhs.

72. The merger of special duty with basic duty results in a rate of Rs. 605 per metric tonne on hessian and of Rs. 385 per metric tonne in the case of other jute products which relate mainly to sacking. I propose to round off these rates to Rs. 600 and Rs. 400 per metric tonne respectively. The regulatory duty will remain unchanged at 50 per cent. The net gain to the Exchequer would be Rs. 1.76 crores of which Rs. 1.20 crores would be by way of regulatory duties.

73. Throughout ages, our spinners and weavers have produced an infinite and ever-changing variety of colour, texture and design to beguile our fancy; and the Central Board of Excise and Customs has had a difficult task in evolving a textile tariff which can keep pace with all the subtle nuances of our textile products. I propose to make one more effort and introduce an extensive rationalisation of the textile tariff which has been worked out after a great deal of detailed examination. Honourable Members would, I am sure, be happy to note that the overall revenue effect of this rationalisation, at any rate, would be insignificant.

74. Finally, I would like to round off by a few concessions in excise duties. In the case of some items, duty-free clearance upto a value of Rs. 50,000 is allowed subject to the proviso that the total clearances from the unit do not exceed Rs. 2 lakhs in a year. In some other cases, clearances upto a value of Rs. 1 lakh are exempted. I propose now to raise the exemption limit in all cases where the lower limit of Rs. 50,000 is allowed today to Rs. 1 lakh subject to the upper ceiling remaining unchanged at Rs. 2 lakhs. This measure which is intended to help the smaller units will cost the Exchequer Rs. 1.40 crores in a full year.

75. Some concessions were introduced in the last Budget to encourage the use of minor oils in the manufacture of soap. In view of the urgent need to reduce our dependence on imports in regard to vegetable oils in general, I propose to increase the incentive by reducing the minimum percentage of use of minor oils from 5 per cent to 3 per cent and by introducing a rate of rebate of Rs. 4.50 per metric tonne on the duty leviable on soap as long as the reduced minimum use of minor oils obtains. This rebate will increase progressively by Rs. 1.50 per tonne for every additional percentage point increase in the utilization of these oils. A similar concession in relation to rice bran oil used in the manufacture of soap at the rate of Rs. 1.50 per tonne for every additional percentage point of use of rice bran oil beyond a minimum level of 15 per cent will also be given.

76. To encourage the use of rice bran oil in the manufacture of vanaspati, the minimum percentage use of 7 per cent which was prescribed last year is being reduced to 1 per cent without any change in the rate of rebate which would remain Rs. 100 per metric tonne on the duty payable on vanaspati produced from such oil. Similarly, the incentive for greater use of cotton-seed oil in the manufacture of vanaspati is also being increased on a graded basis. The present general concession of Rs. 100 per tonne of vanaspati produced from cotton-seed oil will be withdrawn and a minimum compulsory usage of 10 per cent prescribed. Beyond this percentage, however, the rebate would be Rs. 200 per metric tonne upto 20 per cent of usage, Rs. 250 per metric tonne from 20 to 30 per cent of usage and again Rs. 200 per metric tonne beyond 30 per cent of usage. These concessions on oils would cost the exchequer about Rs. 60 lakhs.

77. Honourable Members would be happy to know that I have no proposals this year in regard to postal and telegraph rates. The Finance Bill, however, provides for some changes in the sales-tax law applicable to Delhi to remove certain lacunae which act to the detriment of sales tax revenue accruing to the Delhi Administration.

#### *To Sum up*

78. Taking all the proposals together, the total additional revenue from Excise duties would be of the order of Rs. 145 crores in 1972-73 of which Rs. 97 crores will accrue to the Centre and roughly Rs. 48 crores to the States. In addition, countervailing import duties which will apply in respect of all changes in excise duties other than those relating to iron and steel and aluminium are expected to yield an additional revenue of Rs. 13.40 crores. Other changes in Customs duties will yield, as already mentioned, an additional revenue of Rs. 8.60 crores for the Centre. The additional yield from direct taxes for 1972-73 would be Rs. 14 crores for the Centre and Rs. 2 crores for the States. All in all, the additional revenue at the Centre next year will be of the order of Rs. 133 crores and for the States, Rs. 50 crores. The initial deficit of Rs. 375 crores will thus stand reduced to Rs. 242 crores which I think is a reasonably safe level.

79. Sir, in conclusion, may I express the hope that the Budget proposals I have just presented will be judged in their entirety and against the background of the formidable challenge we continue to face as a nation. The level of investment in the economy needs to be raised substantially at the present juncture. This is necessary not only in the interest of growth, particularly industrial growth, but also for making a tangible impression on the well-being of the most disadvantaged sections of society. We have also to assist Bangladesh in her immediate task of restoring a measure of stability and viability to the economy. Nor can we let down our guard in regard to the security and integrity of the nation. At the same time, deficit financing must be kept within reasonable proportions.

80. Fortunately, the bulk of the unavoidable and indeed necessary increase in outlay next year will be financed by the normal growth in revenues. If I have not been able to avoid additional taxation altogether, I hope Honourable Members would remember that I have not been unduly cautious either in providing a stimulus to growth and social welfare by a substantial increase in Plan outlay. Some of my tax proposals will also serve other objectives such as self-reliance. It is in this sense that I spoke at the outset of quickening the mutually reinforcing process of growth, social justice, self-reliance, investment and resources mobilization. I can only hope that taken in their entirety, the Budget proposals will take the economy one stage forward in its march towards our cherished goals.

I thank you.